अध्याय

11

सेवाएँ: विकास के अवसरों को बढ़ावा देना

पिछले तीन दशकों के उतार-चढ़ाव के दौरान, सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एक मजबूत आधार के रूप में खड़ा रहा है। महामारी के बाद की इसकी गतिशीलता, विशेष रूप से वित्त वर्ष 24 के दौरान उभरे और मजबूत हुए रुझान और पैटर्न, घरेलू सेवा वितरण प्रणालियों और उनकी मांगों में चल रहे परिवर्तन का संकेत देते हैं। नीति और प्रक्रियात्मक सुधारों, भौतिक अवसंरचना और संभार-तंत्र पर ध्यान केंद्रित करने से, सभी महत्वपूर्ण व्यवसाय, व्यक्तिगत, वित्तीय और अवसंरचना-आधारित सेवाएँ महामारी से मजबूती से उभरी हैं। हालाँकि, यह परिवर्तन ऑनलाइन भुगतान, ई-कॉमर्स और मनोरंजन प्लेटफॉर्म जैसी डिजिटल सेवाओं की दिशा में तेजी से हो रहे बदलावों के साथ-साथ अन्य उत्पादक गतिविधियों में इनपुट के रूप में उच्च तकनीकी सेवाओं की मांग में वृद्धि में निहित है। भारत की युवा और तकनीक-प्रेमी आबादी देश के व्यावसायिक और शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र को और बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती है। इससे श्रम बल को समयबद्ध तरीके से आवश्यक डिजिटल और उच्च तकनीक कौशल से लैस किया जा सकेगा, जिससे भारत को इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

परिचय

11.1 भारत के सेवा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिन्हें मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: संपर्क-गहन सेवाएं और गैर-संपर्क-गहन सेवाएँ। पहली श्रेणी में व्यापार, आतिथ्य, परिवहन, रियल एस्टेट, सामाजिक, सामुदायिक और व्यक्तिगत सेवाएँ शामिल हैं। दूसरी में वित्तीय, सूचना प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाएँ, संचार, प्रसारण और भंडारण सेवाएँ शामिल हैं। इस क्षेत्र में लोक प्रशासन और रक्षा सेवाएँ भी शामिल हैं।

11.2 सेवा क्षेत्र भारत की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 24 में अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग 55 प्रतिशत है। मांग और आपूर्ति संबंधी कई कारक सेवा क्षेत्र के निष्पादन को निर्धारित करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वित्त, पर्यटन, आतिथ्य और मनोरंजन जैसी सेवाओं की महत्वपूर्ण घरेलू मांग एक बड़ी और युवा आबादी पर आधारित है। तेजी से हो रहा शहरीकरण परिवहन, आवास, स्वच्छता और उपयोगिता सेवाओं का समर्थन करता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के विस्तार ने संभार-तंत्र, डिजिटल भुगतान और संबंधित सेवाओं के लिए बढ़ी हुई आवश्यकताएँ उत्पन्न की हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक सेवाएँ मध्यावधि में अपनी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति बनाए रखने की संभावना रखती हैं। हालाँकि, अध्ययनों से पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के अनुप्रयोग से व्यावसायिक सेवाओं के विकास के अवसरों में उत्तरोत्तर कमी आने की संभावना है और इसलिए, यह दीर्घकालिक स्थिरता और रोजगार सृजन के लिए एक चुनौती है। इस प्रकार, बड़े और सुस्थापित शहरों के संचयी प्रभावों का लाभ उठाने के लिए मानव पूंजी पर ध्यान केंद्रित करना सेवाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से वैश्विक बाजार क्षमता वाली सेवाओं के लिए।[1]

1. द इकोनॉमिस्ट (24 जून 2024)। क्या सेवाएँ दुनिया को समृद्ध बनाएंगी?
https://www.economist.com/finance-and-economics/2024/06/24/will-services-make-the-world-rich

11.3 सरकार ने एक समर्थकारी वातावरण बनाकर, निवेश को बढ़ावा देकर, कौशल बढ़ाकर और बाजार तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, डिजिटल इंडिया अभियान ने डिजिटल सेवाओं में वृद्धि को बढ़ावा दिया है, निर्यात संवर्धन योजनाओं ने सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित किया है, बुनियादी ढांचे के विकास ने संभार-तंत्र, पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को बढ़ावा दिया है, और कौशल विकास पहलों ने कार्यबल के लिए अधिक अवसर प्रदान किए हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन में लक्षित प्रयासों ने पहुंच और विकास को बढ़ाया है, जिससे भारत के सेवा क्षेत्र के लिए एक आशाजनक भविष्य सुनिश्चित हुआ है।

11.4 अध्याय के शेष खंड देश में उभरते सेवा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित किए गए हैं, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है। निम्नलिखित खंड घरेलू उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार गतिविधि के संदर्भ में सेवा क्षेत्रों के निष्पादन का अवलोकन प्रदान करता है, इसके बाद सेवा क्षेत्र में वित्तीय प्रवाह पर एक खंड है। इसके बाद विभिन्न सेवा उप-क्षेत्रों और संबंधित नीतिगत पहलों के निष्पादन पर गहन चर्चा की गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस सर्वेक्षण के अध्याय 7 में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं में विकास पर चर्चा की गई है। अंतिम खंड में भविष्य के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई है।

सेवा क्षेत्र के निष्पादन का अवलोकन

सेवा क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए)

11.5 महामारी से प्रभावित वित्त वर्ष 2021 को छोड़कर पिछले दशक के सभी वर्षों में सेवा क्षेत्र में 6 प्रतिशत से अधिक की वास्तविक वृद्धि दर देखी गई। वैश्विक स्तर पर, वर्ष 2022 में भारत का सेवा निर्यात दुनिया के वाणिज्यिक सेवा निर्यात का 4.4 प्रतिशत रहा।

चार्ट XI-1: सेवा क्षेत्र में जीवीए की बढ़ती प्रवृत्ति (स्थिर मूल्यों में)

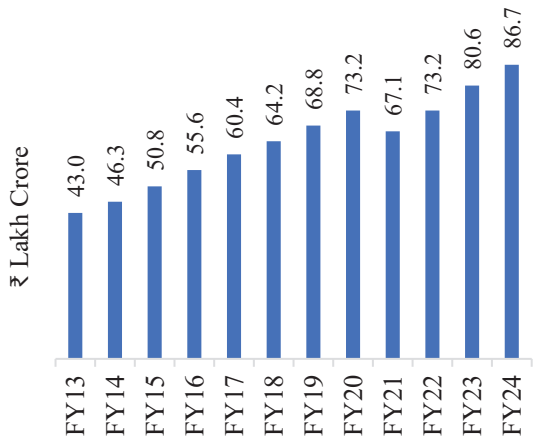

चार्ट XI-2: सेवा क्षेत्र जीवीए में वर्ष-दर-वर्ष (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि में मजबूत गति

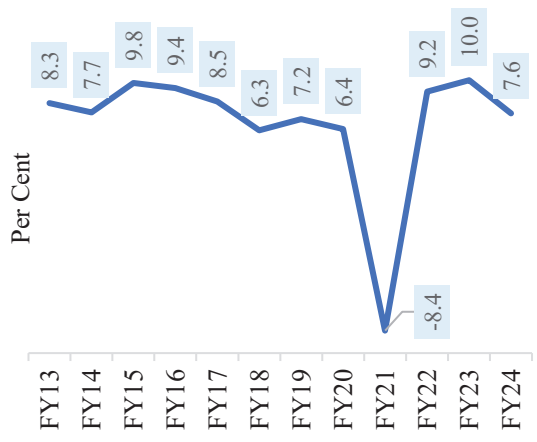

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)
नोट: वित्त वर्ष 23 के लिए प्राक्कलन प्रथम संशोधित प्राक्कलन हैं, और वित्त वर्ष 24 के लिए अनंतिम प्राक्कलन हैं।

11.6 पिछले दशक में समग्र जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान काफी बढ़ गया है। महामारी से प्रेरित संकुचन के कारण वित्त वर्ष 21 में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट आई। हालाँकि, जैसा कि चार्ट XI-3 में दिखाया

गया है, इस क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग कोविड-पूर्व स्तर पर पहुँच गई है।

चार्ट XI-3: कोविड के बाद समग्र जीवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में मजबूती

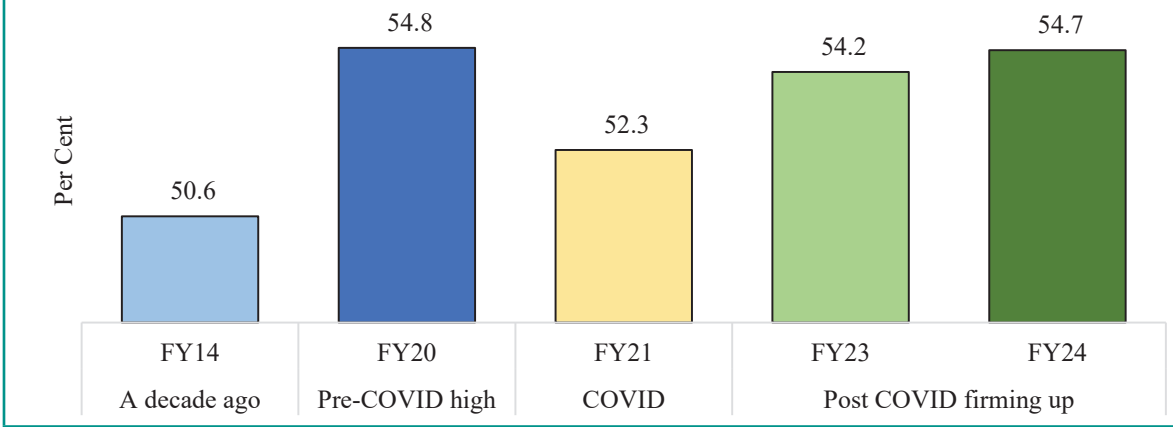

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस), एमओएसपीआई
नोट: जीवीए - सकल मूल्य सवर्धन। वित्त वर्ष 23 के लिए प्राक्कलन प्रथम संशोधित प्राक्कलन हैं, और वित्त वर्ष 24 के लिए अनंतिम प्राक्कलन हैं।

11.7 कोविड से पहले एक दशक तक, सेवा क्षेत्र की वास्तविक वृद्धि दर लगातार समग्र आर्थिक वृद्धि से अधिक रही। हालांकि, वित्त वर्ष 21 में, सेवा क्षेत्र में 8.4 प्रतिशत का तीव्र संकुचन देखा गया, जबकि समग्र जीवीए में 4.1 प्रतिशत की गिरावट आई। गैर-संपर्क गहन सेवाओं, मुख्य रूप से वित्तीय, सूचना प्रौद्योगिकी और पेशेवर सेवाओं ने कुछेक व्यवधानों और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण धनात्मक और स्थिर वृद्धि का अनुभव किया। लॉकडाउन, यात्रा प्रतिबंध और निवारक उपायों के कारण आतिथ्य, मनोरंजन और व्यक्तिगत सेवाओं की मांग में कमी के कारण संपर्क-गहन सेवाओं में संकुचन केंद्रित था। जैसे ही प्रतिबंध हटाए गए, इन क्षेत्रों ने सहायक नीतिगत माहौल की मदद से वापसी की। इसलिए, कोविड के बाद, सेवा क्षेत्र की वृद्धि ने वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 में समग्र जीवीए वृद्धि को पीछे छोड़ दिया, जिससे अर्थव्यवस्था के ऊपर की ओर बढ़ाने में पुनः इसकी भूमिका रही।

चार्ट XI-4 सेवा क्षेत्र में व्यापक-आधारित वृद्धि

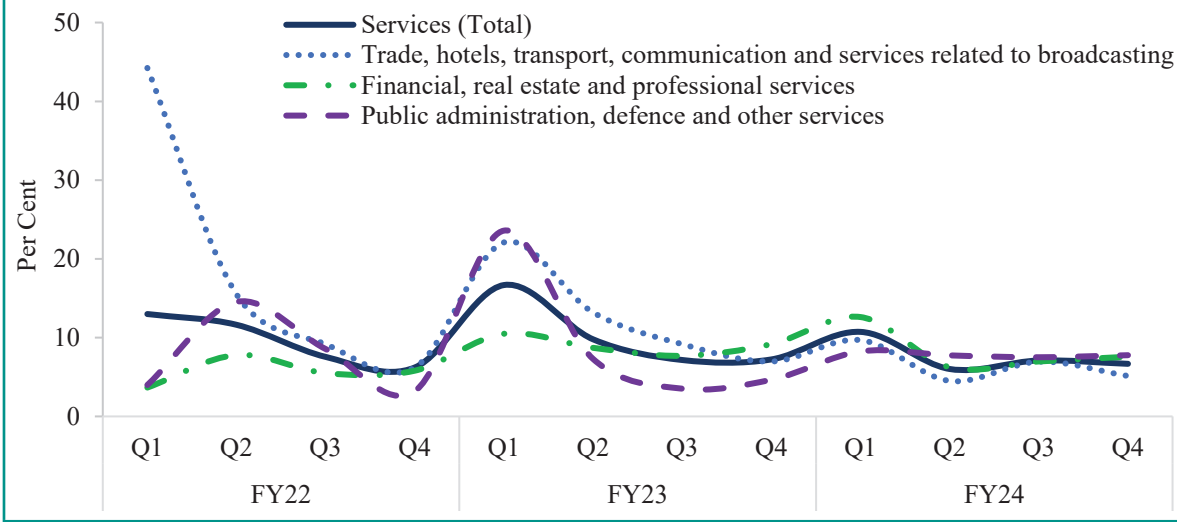

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस), एमओएसपीआई

11.8 अनंतिम अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 24 में सेवा क्षेत्र में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतक सेवा क्षेत्र की वृद्धि की कहानी का समर्थन करते हैं। जीएसटी संग्रहण और ई-वे बिल निर्गम करने दोनों ने थोक और खुदरा व्यापार को दर्शाते हुए दोहरे अंकों की वृद्धि प्रदर्शित की। वित्त वर्ष 24 में सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़[2] रूपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, और मजबूत घरेलू व्यापार गतिविधि को रेखांकित करता है। औसत दैनिक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, प्रबंधित कुल हवाई यात्री और रेल माल-भाड़ा यातायात ने वित्त वर्ष 24 में वर्ष-दर-वर्ष क्रमशः 18.9 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की, जो परिवहन सेवाओं की स्थिर वृद्धि का समर्थन करती है। हालांकि व्यापार, होटल और परिवहन क्षेत्र के स्तरों में महामारी-पूर्व की प्रकृत्ति में रही कमी को प्राप्त किया जाना बाकी है जैसाकि इस सर्वेक्षण के अध्याय 1 के बॉक्स XI.1 में दर्शाया गया है। मार्च, 2024 तक बैंक ऋण और जमाओं में वर्ष-दर-वर्ष क्रमशः 20.2 प्रतिशत और 12.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वित्तीय सेवाओं में निरंतर उछाल का संकेत देती है। आवासीय संपत्ति बाजार ने भी 2023 में एक आशाजनक प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया, जिसमें मांग और नई आपूर्ति में दोहरे अंकों की वृद्धि का देखी गई।[3]

बॉक्स XI-1: पंजीकृत कंपनियों की संख्या में सेवा क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक बना हुआ है।

31 मार्च 2024 तक भारत में कुल 16,91,495 सक्रिय कंपनियाँ मौजूद हैं। सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय कंपनियाँ (65 प्रतिशत) हैं। सेवा क्षेत्र में, व्यावसायिक सेवा में सबसे ज्यादा सक्रिय कंपनियाँ (28 प्रतिशत) हैं, उसके बाद ट्रेडिंग (13 प्रतिशत) और सामुदायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएँ (11 प्रतिशत) हैं। अकेले वित्त वर्ष 24 में 1,85,312 नई कंपनियाँ पंजीकृत हुई, जिनमें से 71 प्रतिशत सेवा क्षेत्र की कंपनियाँ थीं।[4]

चार्ट XI-5: सक्रिय कंपनियों का आर्थिक गतिविधि-वार वितरण

(31 मार्च 2024 को यथास्थिति)

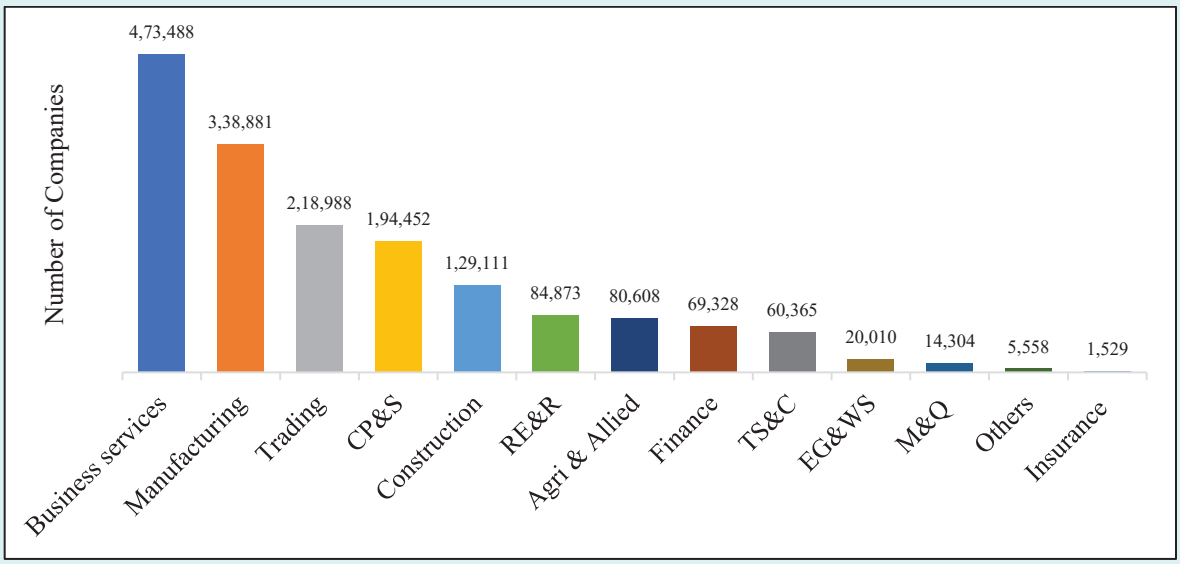

स्रोत: मासिक सूचना बुलेटिन (मार्च 2024), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

नोट: सीपीएंडएस - सामुदायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएँ, कृषि और संबद्ध - कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ, आरईएंडआर - रियल एस्टेट और किराए-दारी, टीएसएंडसी - परिवहन, भंडारण और संचार, ईजीएंडडब्ल्यूएस - बिजली, गैस और जल आपूर्ति कंपनियाँ, एमएंडक्यू - खनन और उत्खनन। सेवा क्षेत्र की कंपनियों में ट्रेडिंग, व्यावसायिक सेवाएँ, सीपीएंडएस, टीएसएंडसी, आरईएंडआर, वित्त और बीमा शामिल हैं।

2. वित्त मंत्रालय की दिनांक 01 अप्रैल 2024 की पीआईबी रिलीज। https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2016802

3. प्रॉप टाइगर (04 जनवरी 2024)। 2023 में नए घरों की बिक्री में 33% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई: प्रॉप टाइगर.कॉम रिपोर्ट। https://www.proptiger.com/guide/post/new-home-sales-record-33-yoy-growth-in-2023-proptiger-com-report

4. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय. मासिक सूचना बुलेटिन (मार्च, 2024). https://www.mca.gov.in/bin/dms getdocument?mds=jRBDSS%252FnmHQx-90z9wOfBCA%253D%253D&type=open

सेवा क्षेत्र में रुचि बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारक डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं की बढ़ती हिस्सेदारी है, जिसने वैश्विक निर्यात में तेजी से वृद्धि देखी है। सेवा क्षेत्र का तेजी से औपचारिकीकरण, डिजिटल, वित्तीय और मनोरंजन सेवाओं की बढ़ती मांग, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण और स्टार्ट-अप के लिए कुशल पेशेवरों की उपलब्धता अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा दे रही है।

क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) - सेवाएं

11.9 भारत में सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि ने दुनिया भर में महामारी और अन्य व्यवधानों और बाधाओं को पार कर लिया। अप्रैल, 2023 से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और पूरे वित्तीय वर्ष में यह लचीला बना रहा। एचएसबीसी का इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई)[5] एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उच्च-आवृत्ति संकेतक है जो समग्र सेवा क्षेत्र की वृद्धि के विचार का समर्थन करता है। मार्च 2024 में, सेवा पीएमआई बढ़कर 61.2 हो गई, जो लगभग 14 वर्षों में इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बिक्री और व्यावसायिक गतिविधि विस्तार में से एक है। यह मुख्य रूप से स्वस्थ मांग दशाओं, दक्षता लाभ और सकारात्मक बिक्री घटनाक्रमों के कारण व्यावसायिक गतिविधि में मौजूदा उछाल के परिणामस्वरूप हुआ। वित्त वर्ष 2024 में पीएमआई सेवाओं का औसत पूरे वर्ष के लिए 60.3 रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 57.3 था।[6] जैसा कि चार्ट XI.6 से देखा जा सकता है, अगस्त, 2021 से सेवा पीएमआई 50 से ऊपर बनी हुई है, जिसका अर्थ है पिछले 35 महीनों से निरंतर विस्तार होना। गतिशील बाजार स्थितियों के बीच इस क्षेत्र का विस्तार जारी रहा है।

चार्ट XI-6: वैश्विक उतार-चढ़ाव के बीच वित्त वर्ष 24 में पीएमआई सेवाओं ने नई ऊंचाइयों को छुआ

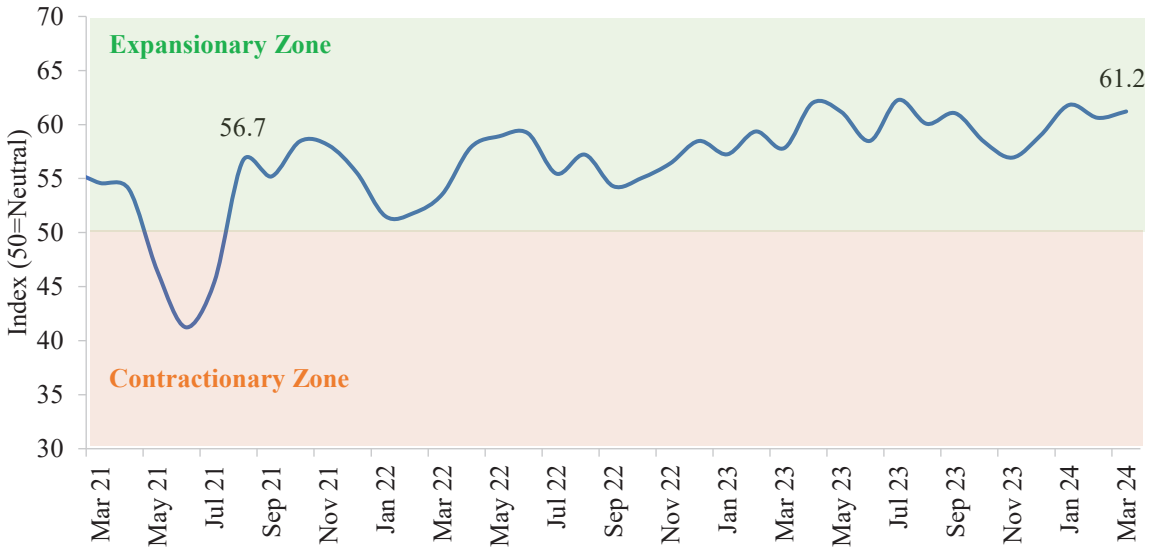

स्रोत: विभिन्न मासिक एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई रिपोर्टों से संकलित
नोट: यह सूचकांक 0 से 100 के बीच भिन्न-भिन्न है और 50 से ऊपर रीडिंग पिछले मास की तुलना में समग्र वृदिध और 50 से नीचे रीडिंग समग्र कमी का संकेत करती है।

5. सेवा पीएमआई में उपभोक्ता (खुदरा को छोड़कर), परिवहन, सूचना, संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं।
6. एसएंडपी ग्लोबल (04 अप्रैल 2024)। एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई। https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/5964f1602e374900a1b109fcefe7e2f3

सेवा क्षेत्र में व्यापार

11.10 पिछले तीन दशकों में भारत के सेवा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात से आगे निकल गया है और वैश्विक निर्यात का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। महामारी के बाद, सेवा निर्यात ने स्थिर गति बनाए रखी है। वित्त वर्ष 24 में भारत के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान 44 प्रतिशत था।

11.11 वैश्विक व्यापार के कमजोर पड़ने से वित्त वर्ष 24 के दौरान भारत के सेवा निर्यात पर असर पड़ा, जिसमें वृद्धि एक साल पहले 27.8 फीसदी से घटकर 4.8 फीसदी रह गई। हालांकि, सेवा निर्यात में भारत पांचवें[7] स्थान पर रहा और अन्य देश यूरोपीय संघ (इंट्रा-ईयू व्यापार को छोड़कर), संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन हैं। कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में भारत के सेवा निर्यात का लगभग 73 प्रतिशत हिस्सा है और वित्त वर्ष 24 तक वर्ष-दर-वर्ष इसमें 9.6 प्रतिशत वृद्धि देखी गई। यात्रा सेवाओं के निर्यात में 24.6 प्रतिशत की वार्षिक उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसे महामारी प्रतिबंधों के बाद पर्यटन में निरंतर सुधार का लाभ मिला। इसके विपरीत, परिवहन प्राप्तियों में 19.1 प्रतिशत की गिरावट आई, जो मुख्य रूप से वैश्विक माल ढुलाई दरों में कमी के कारण थी, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स[8] के औसत मैं भी गिरावट देखी गयी, जिसमें वित्त वर्ष 24 के दौरान किसी वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 3.9 प्रतिशत तक गिरावट आई।

चार्ट XI.7: सेवाओं के अंतर्गत चार प्रमुख उप-क्षेत्रों का निर्यात में योगदान

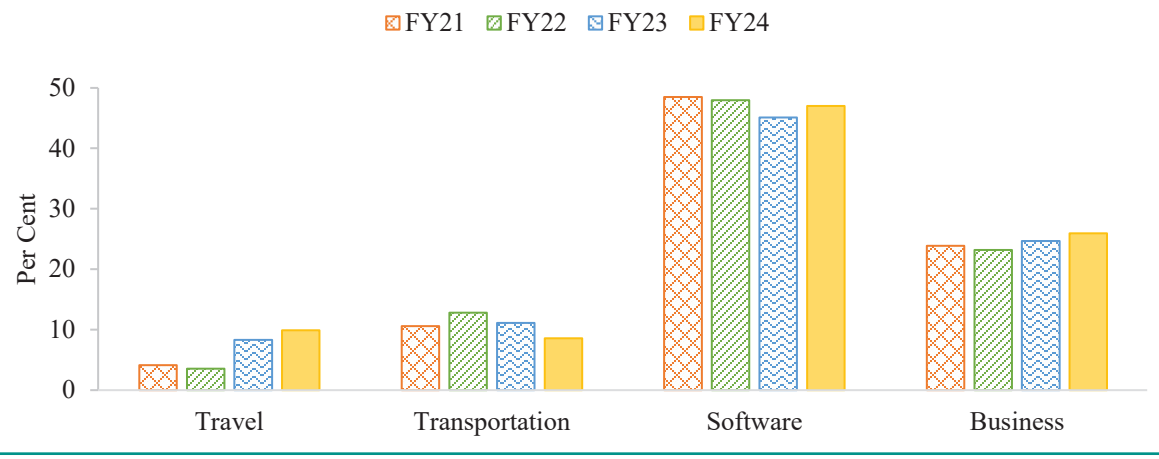

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था पर आरबीआई सांख्यिकी पुस्तिका (तालिका संख्या 196 - भारत का समग्र भुगतान संतुलन- त्रैमासिक- अमेरिकी डॉलर), आरबीआई-भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस
नोट: चार्ट में प्रस्तुत नहीं की गई अन्य सेवाओं में शामिल हैं- बीमा, सरकार अन्यत्र शामिल नहीं (जी.एन.आई.ई.), विविध, वित्तीय और संचार सेवाएं।

11.12 हाल ही में, 'अन्य व्यावसायिक सेवाओं' खंड में वृद्धि मुख्य रूप से व्यापार और प्रबंधन परामर्श, जनसंपर्क, इंजीनियरिंग सेवाओं, विज्ञापन, व्यापार मेला सेवाओं और वैज्ञानिक और अंतरिक्ष सेवाओं सहित अन्य तकनीकी सेवाओं जैसे क्षेत्रों द्वारा उत्प्रेरित है। दक्षता लाभ और कम व्यावसायिक लागत की आशा करने वाले बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा ने सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात को काफी बढ़ावा दिया है। पिछले कुछ वर्षों में, यात्रा और व्यावसायिक सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है जबकि परिवहन में मामूली गिरावट आई है। इसके अलावा, महामारी ने डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं की ओर

7. विश्व व्यापार संगठन। (2023)। विश्व व्यापार सांख्यिकीय समीक्षा 2023 (पृष्ठ 63)। https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wts-r_2023_e.pdf

8. बाल्टिक ड्राई इंडेक्स (बीडीआई) एक ऐसा इंडेक्स है जो सीमेंट, कोयला, लौह अयस्क और अनाज जैसे ड्राई बल्क कार्गो को बल्क फ्रेटर पर ले जाने की कीमत को ट्रैक करता है। चूंकि इनमें से कई वस्तुएं कच्चे माल के रूप हैं जो तैयार माल के उत्पादन में इस्तेमाल होती हैं, इसलिए बीडीआई को अक्सर आर्थिक विकास और उत्पादन का संकेतक माना जाता है। यह संकेतक लंदन स्थित बाल्टिक एक्सचेंज द्वारा अनुरक्षित किया जाता है।

वैश्विक मांग में संरचनात्मक बदलाव को उत्प्रेरित किया है। परिणामस्वरूप, वैश्विक स्तर पर डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2019 में 4.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 6.0 प्रतिशत हो गई।[9]

11.13 वित्त वर्ष 24 के दौरान, सेवाओं का आयात 178.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 2.1 प्रतिशत की कमी हुई और वैश्विक माल ढुलाई दरों में कमी के कारण इसमें कमी आई है। सेवाओं के निर्यात में वृद्धि और आयात में गिरावट के कारण वित्त वर्ष 24 के दौरान पिछले साल के मुकाबले निवल सेवा प्राप्तियों में वृद्धि हुई, जिससे भारत के चालू खाता घाटे को थामने में मदद मिली।

सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के लिए वित्तपोषण स्रोत

11.14 सेवा क्षेत्र घरेलू स्तर पर घरेलू बैंकों और पूंजी बाजारों से ऋण के माध्यम से और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के माध्यम से अपनी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करता है। निम्नलिखित खंड विस्तार से बताता है कि सेवा क्षेत्र किस प्रकार अपना वित्तपोषण प्राप्त करता है।

बैंक ऋण

11.15 वित्त वर्ष 24 में सेवा क्षेत्र में ऋण प्रवाह में तेजी देखी गई, जिसमें अप्रैल, 2023 से प्रत्येक माह वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर 20 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर गई। वित्तीय वर्ष 22.9 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ मार्च, 2024 में 45.9 लाख करोड़ रुपये के बकाया सेवा क्षेत्र ऋण के साथ समाप्त हुआ।[10]

चार्ट XI.8: वित्त वर्ष 24 में मजबूत बैंक ऋण निर्माण और वृद्धि

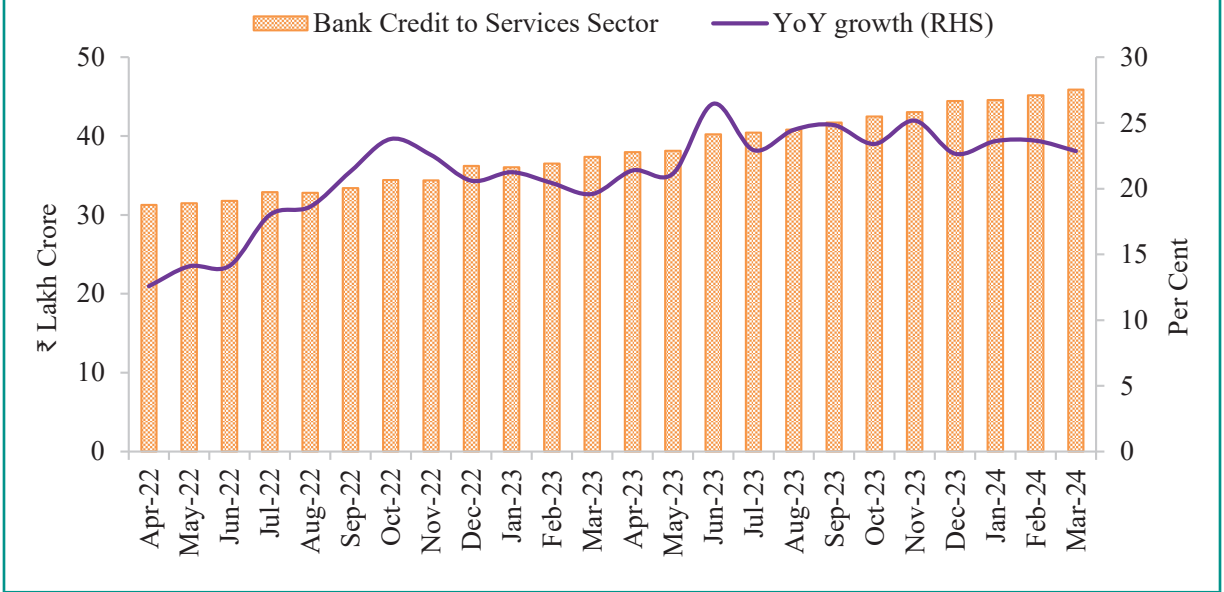

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था पर आरबीआई की सांख्यिकी पुस्तिका (तालिका संख्या 170 प्रमुख क्षेत्रों द्वारा बैंक ऋण का अभिनियोजन), भारतीय अर्थव्यवस्था पर आरबीआई-डेटाबेस

9. विश्व व्यापार संगठन। (2024)। व्यापार दृष्टिकोण 2024। (परिशिष्ट तालिका 5: डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के अग्रणी निर्यातक, 2023) https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtsr_2023_e.pdf

10. आरबीआई की मौद्रिक नीति रिपोर्ट (अप्रैल, 2024) https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=22435

11.16 सेवा क्षेत्र को ऋण, परिवहन संचालकों, पर्यटन, होटल और रेस्तरां, विमानन, व्यावसायिक सेवाओं, व्यापार और वाणिज्यिक रियल इस्टेट जैसे उप-क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हुआ। विमानन क्षेत्र में 56 प्रतिशत की सबसे महत्वपूर्ण वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई, जिसका श्रेय विमान पट्टाकरण, किराएदारी और धनात्मक माध्यम से दीर्घकालिक विकास संभावना में वृद्धि को दिया जाता है।

बाह्य वित्तपोषण

11.17 व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 (डब्ल्यू आई आर 2024) प्रकाशित की है और वर्ष 2023 के लिए एफडीआई अंतवृद्धि (शीर्ष 20 मेजबान अर्थव्यवस्थाएं) के संबंध में भारत को 15वां स्थान दिया है। डब्ल्यूआईआर 2024 के अनुसार, भारत अंतरराष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों की संख्या के संबंध में दूसरा सबसे बड़ा और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट घोषणाओं की संख्या के संबंध में चौथा सबसे बड़ा मेजबान देश है।

11.18 वित्त वर्ष 2024 में सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में गिरावट देखी गई (चार्ट XI-9), जैसा कि भारत में समग्र एफडीआई इक्विटी प्रवाह के मामले में हुआ। यह गिरावट कई कारणों का परिणाम थी। उच्च ब्याज दरें, भू-राजनीतिक संघर्ष, बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितताएं और घरेलू सोर्सिंग के पक्ष में बढ़ते संरक्षणवाद, इन सभी की इस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह को कम करने में भूमिका है।

चार्ट XI.9: सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में नरमी

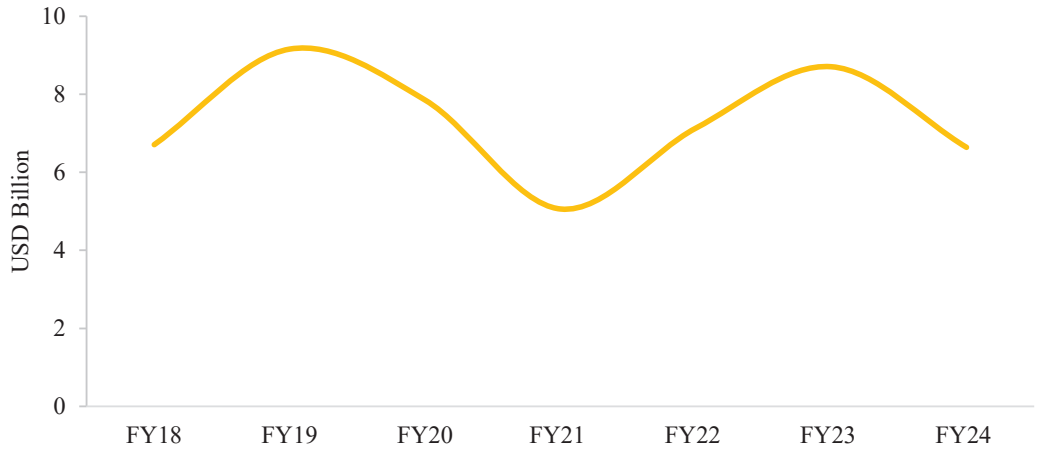

स्रोत: डीपीआईआईटी प्रकाशन- त्रैमासिक एफडीआई सांख्यिकी से प्राप्त।
नोट: (i) सेवा क्षेत्र में वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय/व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कूरियर, तकनीकी परीक्षण एवं विश्लेषण, अन्य शामिल हैं।
(ii) वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 के लिए मान अनंतिम हैं।

11.19 वित्त वर्ष 2024 में कुल बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) प्रवाह में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 53 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2024 में इस क्षेत्र को 14.9 बिलियन अमरीकी डॉलर का अंतर्वाह हुआ, जिससे वित्त वर्ष 2023 में 23.3 प्रतिशत की वृद्धि के विपरीत 58.3 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।[12]

प्रमुख सेवाएँ: क्षेत्रवार निष्पादन

भौतिक कनेक्टिविटी-आधारित सेवाएँ

11.20 विविध अवसंरचना नेटवर्क में माल, लोगों और सूचनाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अनेक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। परिवहन सेवाओं में व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है, जिसमें ट्रेनों, बसों, टैक्सियों और एयरलाइनों

11. संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)। (2023)। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023। https://unctad.org/publication/world-investment-report-2023

12. स्रोत : आरबीआई डेटा की निकटम संभव औद्योगिक वर्गीकरण से मैपिंग की जाती है।

के माध्यम से यात्री परिवहन से लेकर शिपिंग कंपनियों, फ्रेट फॉरवर्डर्स और कूरियर सेवाओं द्वारा सुगम माल परिवहन शामिल है। वाहन रखरखाव और विमानपत्तनों की ग्राउंड हैंडलिंग जैसी सहायक सेवाएँ इन परिवहन पेशकशों को और भी बेहतर बनाती हैं। आपूर्ति श्रृंखलाओं को अनुकूलित करने में संभार-तंत्र सेवाएँ महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित खंड सड़क, रेलवे, जलमार्ग और वायुमार्ग में दी जाने वाली सेवाओं पर प्रकाश डालते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि इन क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना के निर्माण में प्रगति को अध्याय 12 में शामिल किया गया है और यहाँ दोहराया नहीं गया है।

सड़क मार्ग

11.21 भारत में माल का एक बड़ा हिस्सा सड़क मार्ग से परिवहन किया जाता है। इसलिए, राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर उपयोगकर्ता सुविधा में सुधार करना समग्र एनएच गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। टोल डिजिटलीकरण ने टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को काफी हद तक कम कर दिया है, जो 2014 में 734 सेकंड से घटकर 2024 में 47 सेकंड रह गया है। स्वचालित नंबर प्लेट पहचान और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से फ्री फ्लो टोलिंग जैसी पहलों ने टोलिंग दक्षता को बढ़ाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए एक व्यापक '4ई' रणनीति - इंजीनियरिंग (सड़कें और वाहन), एनफोर्समेंट (प्रवर्तन), इमरजेंसी केयर (आपातकालीन देखभाल) और एजुकेशन (शिक्षा) - भी तैयार की है। सरकार ने नेटवर्क नियोजन और संकुलता के अनुमानों के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल का उपयोग किया है, जो भविष्य की परिवहन मांग का अनुमान लगाने और संभार-तंत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए ई-वे बिल और फास्टैग से बड़ी मात्रा में डेटा का लाभ उठाता है। एक्सेस नियंत्रित उच्च गति कोरिडोर के विकास पर फोकस से एनएच नेटवर्क की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा है। एक्सप्रेसवे और आर्थिक गलियारों के विकास से यात्रा का समय काफी कम हो रहा है और इस प्रकार आर्थिक विकास बढ़ रहा है।[13] राजमार्गों के विकास में असाधारण सुधारों का विवरण इस समीक्षा के अध्याय 12 में सड़क परिवहन खंड में दिया गया है।

11.22 भारत में सड़क सेवाओं को राजमार्गों के किनारे निरंतर रिबन विकास और डिजिटल भूमि अभिलेखों की धीमी गति जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे परियोजना के निष्पादन में देरी होती है। हालाँकि, सड़क परिवहन और सरकार इन मुद्दों का सक्रिय रूप से समाधान कर रहा है, जिसमें पहुँच-नियंत्रित राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने और मौजूदा राजमार्गों को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रवर्तन के लिए समर्पित ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था लागू करना और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस को अपनाना भारत के परिवहन नेटवर्क में सड़क सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों का समाधान करने से सड़क अवसंरचना की पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद मिलेगी।

भारतीय रेलवे

11.23 भारतीय रेलवे (आईआर) उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, रेल प्रणाली को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और विकसित भारत के लिए क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से कई सेवाएँ प्रदान करता है। वित्त वर्ष 24 में भारतीय रेलवे से यात्री यातायात 673 करोड़ था (अनंतिम वास्तविक), जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5.2 प्रतिशत अधिक है। भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 24 में 158.8 करोड़ टन राजस्व-अर्जक माल ढोया (कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को छोड़कर), जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। क्षमता वर्धन, नए चल स्टॉक और प्रचालनिक दक्षताओं में सुधार पर विशेष गौर के साथ भारतीय रेलों के मालभाड़ा लदानों ने वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 24 के दौरान 7.1 प्रतिशत की सीएजीआर प्राप्त की। भारतीय रेल से संबंधित अन्य विवरण इस समीक्षा के अध्याय 12 के रेल परिवहन खंड में दिया गया है।

13. पीआईबी विज्ञाप्ति दिनांक 5 जनवरी, 2024। एमओआरटीएच। https://pib-gov-in/PressRelease/framePage.asox?PRID=1993425

चार्ट XI.10: रेलवे माल यातायात में निरंतर प्रगति

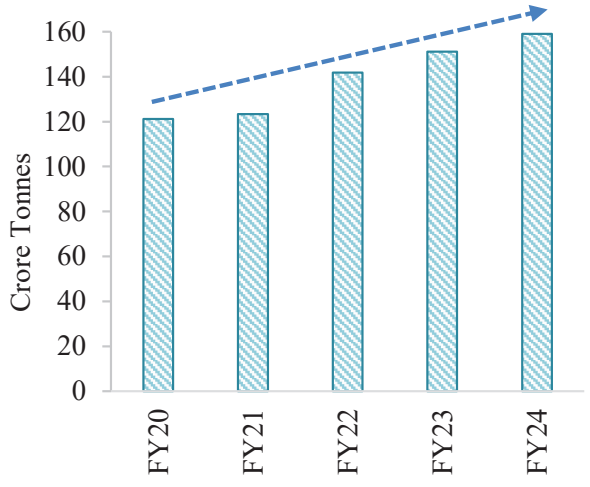

चार्ट XI.11: कोविड के बाद रेलवे यात्री यातायात में सुधार

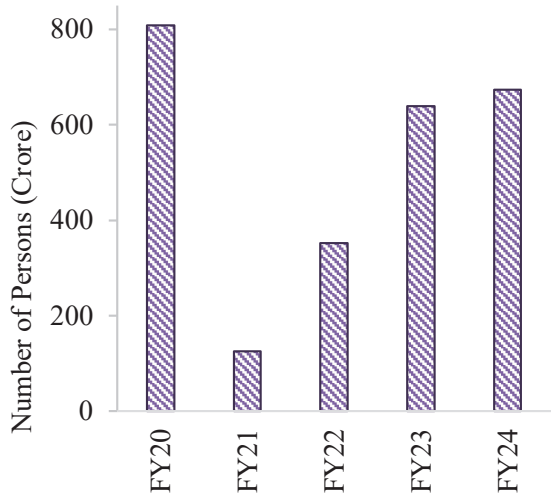

स्रोत: रेल मंत्रालय
नोट: वित्त वर्ष 24 के मान अनंतिम हैं और विवरण 7क के अनुसार, भारतीय रेलवे का मासिक सांख्यिकीय विवरण है।

11.24 यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए रेलवे ने 6108 स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा शुरू की है, जिससे ग्रामीण और शहरी नागरिकों के बीच डिजिटल खाई को पाटा जा रहा है। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली देश और एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइटों में से एक बन गई है, और यह वेबसाइट, मोबाइल ऐप और आईआरसीटीसी अधिकृत एजेंटों के माध्यम से आसानी से सुलभ है। माल-भाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली माल-भाड़ा परिचालन के सभी पहलुओं का व्यापक रूप से प्रबंधन करती है, जिसमें बुकिंग, इलेक्ट्रॉनिक मांग पंजीकरण, रेलवे रसीदों का हस्तांतरण और माल की ट्रैकिंग शामिल है। ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेल सुगम ऐप और फ्रेट बिजनेस डवलपमेंट पोर्टल भी बनाया गया है।

11.25 भारतीय रेलवे की रेलगाड़ी प्रबंधन प्रणाली रियल टाइम ट्रेन आईडी के साथ चलने वाली ट्रेनों का व्यापक दृश्य प्रस्तुत करती है। यह बेहतर नियोजन और आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया के माध्यम से ट्रेन की समयबद्धता में योगदान देता है। लोकोमोटिव, कोच और वैगनों को लोकोमोटिव एसेट मैनेजमेंट, कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम और फ्रेट वैगन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे अनुप्रयोगों द्वारा डिजिटल किया गया है। रेलवे की वित्त प्रणाली आईटी-सक्षम है। बिल पासिंग पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें 99.9 प्रतिशत व्यय और 90 प्रतिशत से अधिक राजस्व लेनदेन कैशलेस हैं। भारतीय रेल ने सामग्री प्रबंधन के लिए एक व्यापक आईटी प्रणाली के माध्यम से अपनी खरीद को डिजिटल कर दिया है जिसे भारतीय रेलवे ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम और एकीकृत सामग्री प्रबंधन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। रेलवे की मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पूरी तरह से स्वचालित और केंद्रीकृत पेरोल, पेंशन, कर्मचारी स्व-सेवा, निष्पादन मूल्यांकन, पास, ई-सेवा रिकॉर्ड, भविष्य निधि आदि प्रदान करती है।

11.26 क्षमता निर्माण के लिए, भारतीय रेलवे ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने कर्मियों के लिए आठ अखिल भारतीय रेलवे-केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। वित्त वर्ष 24 में लगभग 6.5 लाख रेलवे कर्मिकों ने प्रशिक्षण लिया है। रेलवे ने आई-जीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर रेलवे-विशिष्ट शिक्षण सामग्री भी विकसित की है, जहाँ इसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारी ऑन-बोर्ड हैं, और वर्तमान में, लगभग 12 प्रतिशत कम-से-कम एक पाठ्यक्रम में नामांकित हैं।

पत्तन, जलमार्ग और पोत परिवहन

11.27 निर्णयन प्रक्रिया के बढ़ते विकेंद्रीकरण, पेशेवर विशेषज्ञता के एकीकरण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को अपनाने से पत्तनों के प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार हुआ है और मजबूती मिली है। पत्तन क्षेत्र दैनिक पोत और कार्गो संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए सागर सेतु एप्लिकेशन का लाभ उठा रहा है, जो सभी समुद्री व्यवसायों के लिए एक केंद्रीय हब बनने की आकांक्षा रखता है। सागर सेतु भारत के सभी 13 प्रमुख बंदरगाहों के साथ-साथ 22 गैर-प्रमुख बंदरगाहों और 28 निजी टर्मिनलों के साथ भी एकीकृत है।

11.28 राष्ट्रीय जलमार्गों पर नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। मालवाहक जहाजों के विकास से पर्यटक जहाजों को भी लाभ मिलता है, क्योंकि बेहतर जलमार्ग और सुविधाओं से उनके प्रचालनों में वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 24 के दौरान क्रूज यात्राओं में 100 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। लाइटहाउस भी महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण के रूप में उभर रहे हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, समुद्र तट के किनारे 75 लाइटहाउसों और संग्रहालयों के निर्माण की योजना पर काम चल रहा है।

चार्ट XI.12: पोत परिवहन टन भार में निरंतर वृद्धि

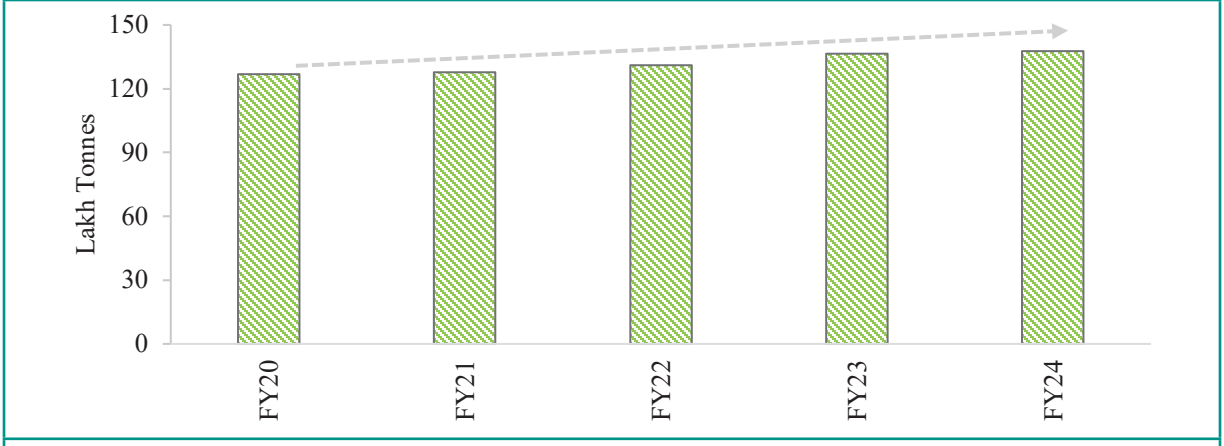

स्रोत: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

वायुमार्ग

11.29 भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है और वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रमुख विमानन बाजारों में से एक है। भारत में विमानन क्षेत्र ने काफी वृद्धि दिखाई है, वित्त वर्ष 2024 में भारतीय हवाई अड्डों पर कुल हवाई यात्रियों की संख्या में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 37.6 करोड़ हो गया है।

11.30 वित्त वर्ष 2024 में प्रबंधित घरेलू हवाई यात्री यातायात में 13 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई और यह 30.6 करोड़ हो गया और अंतरराष्ट्रीय प्रबंधित हवाई यात्रियों की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष आधारित 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 7 करोड़ हो गई। कोविड-19 के प्रभाव से वित्त वर्ष 23 में अंतरराष्ट्रीय संपर्क में कम सुधार के कारण अंतरराष्ट्रीय यातायात में वृद्धि घरेलू यातायात वृद्धि की तुलना में अधिक रही। कोविड-पूर्व स्तरों की तुलना में वित्त वर्ष 23 में घरेलू यात्री यातायात में 98 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुधार 86 प्रतिशत रहा। वित्त वर्ष 24 में भारतीय हवाई अड्डों पर एयर कार्गो की हैंडलिंग वर्ष-दर-वर्ष आधारित 7 प्रतिशत से बढ़कर 33.7 लाख टन हो गई।

11.31 भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में बढ़ती मांग, बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि, पर्यटन, उच्च प्रयोज्य आय, अनुकूल जनसांख्यिकी और विमानन अवसंरचना की अधिक पैठ के कारण जबरदस्त संभावनाएं हैं। प्रगति-मूलक सरकारी नीतियां इस विकास गति को और अधिक समर्थन देती हैं। सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है और

एक ठोस पूंजीगत व्यय योजना द्वारा समर्थित यात्री हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने के लिए नए टर्मिनल भवनों का संचालन किया है। क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के लिए, 2016 में शुरू की गई 'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) योजना[14] ने अपनी शुरुआत से ही 85 अनारक्षित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों को जोड़ने वाले विभिन्न 579 क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) मार्गों पर 141 लाख से अधिक घरेलू यात्रियों को यात्रा की सुविधा प्रदान की।

चार्ट XI.13: हवाई माल यातायात में वृद्धि

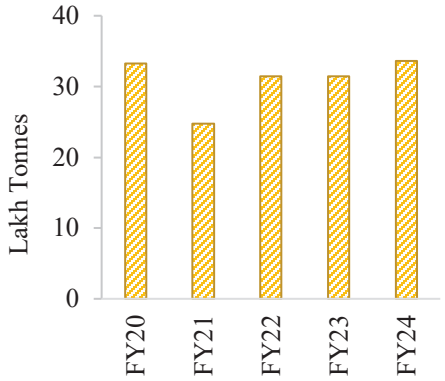

चार्ट XI.14: हवाई यात्री यातायात में तीव्र वृद्धि

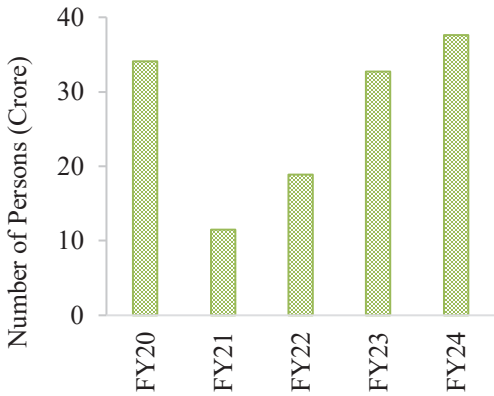

स्रोत: नागर विमानन मंत्रालय

11.32 डिजी-यात्रा[15] जैसी पहल तकनीक के माध्यम से दक्षता बढ़ा रही है। इसके लॉन्च होने के बाद से, 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को इस कार्यक्रम से लाभ मिला है। इसे सभी हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना है।

11.33 भारत में विमानन सेवाओं का भविष्य रखरखाव, मरम्मत और प्रचालन (एमआरओ) क्षेत्र और तेजी से बढ़ते ड्रोन उद्योग के विकास पर टिका हुआ है। भारत का लक्ष्य 2030 तक उदार नियमों और प्रोत्साहनों के साथ वैश्विक ड्रोन हब बनना है। हाल की प्रगति में प्रशिक्षण संगठनों में वृद्धि, रिमोट पायलट प्रमाणपत्र, पंजीकृत ड्रोन और स्वीकृत ड्रोन मॉडल शामिल हैं। गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के प्रोत्साहन ने विमानन पट्टाकरण और वित्तपोषण की सुविधा प्रदान की है, जिसका उदाहरण एयर इंडिया द्वारा हाल ही में विमान अधिग्रहण है। 31 मार्च 2024 तक, 27 संस्थाओं ने विमान पट्टे पर देने के व्यवसाय के लिए पंजीकरण कराया है और 20 से अधिक विमानों का पट्टाकरण किया है, जो इस क्षेत्र के आशाजनक परिदृश्य को दर्शाता है।

11.34 आर्थिक विकास के लिए विमानन उद्योग का विकास और हवाईअड्डों की क्षमता का विस्तार करना आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप स्थिरता संबंधी चिंताएँ और अधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता उत्पन्न होती है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अनुसार, भारत में विभिन्न एयरलाइनों में लगभग 10,000 पायलट हैं।[16] भारतीय विमानन क्षेत्र सकारात्मक रूप से आगे निकल गया है, और देश के पायलटों में महिलाओं की संख्या 15 प्रतिशत है, जो वैश्विक औसत से लगभग तीन गुना अधिक है, इस प्रकार इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए अधिक अवसर प्रस्तुत होते हैं।[17]

14. उड़ान योजना का उद्देश्य छोटे और मध्यम शहरों को हवाई सेवा के माध्यम से बड़े शहरों से जोड़ना है। उड़ान योजना के तहत, 'फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट' से एक घंटे की यात्रा या हेलीकॉप्टर से लगभग 500 किलोमीटर की आधे घंटे की यात्रा के लिए हवाई किराया ₹4000 तय किया गया है।
15. डिजी यात्रा विभिन्न जांच चौकियों, जैसे चेक-इन, सुरक्षा और बोर्डिंग गेट पर यात्रियों की पहचान सत्यापित करने के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करती है, और इसके लिए भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती।
16. पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 23 मार्च 2023, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)। https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx-?PRID=1909941
17. पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी 2024, प्रधानमंत्री कार्यालय। https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1997799

वर्ष 2023 में कुल 1622 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी किए गए, जिनमें से 18 प्रतिशत महिलाओं को जारी किए गए। नागर विमानन मंत्रालय और उससे जुड़े संगठनों ने देश में पायलटों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहले चरण में पांच हवाई अड्डों अर्थात् बेलगावी, जलगांव, कलबुर्गी, खजुराहो और लीलाबाड़ी पर नौ नए उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) के लिए और दूसरे चरण में पांच हवाई अड्डों अर्थात् भावनगर, हुबली, कडप्पा, किशनगढ़ और सेलम पर छह और एफटीओ के लिए अवार्ड पत्र जारी किए।[18] इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं, जिसके लिए सरकार, उद्योग हितधारकों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। अवसंरचना, कौशल विकास और संधारणीयता पहलों में निवेश भारत में विमान क्षेत्र के भविष्य के विस्तार को बढ़ावा देगा।

पर्यटन

11.35 भारत में पर्यटन क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक (टीटीडीआई) 2024 में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है।[19] महामारी के बाद पुनरुद्धार के सकारात्मक संकेत दिखाते हुए, इस उद्योग ने 2023 में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों[20] का आगमन देखा, जो कि वर्ष-दर-वर्ष 43.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। भारत ने पर्यटन के माध्यम से 2.3 लाख करोड़ रूपये से अधिक की विदेशी मुद्रा प्राप्तियां अर्जित की हैं, जो कि वर्ष-दर-वर्ष 65.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। विश्व पर्यटन प्राप्तियों में भारत की विदेशी मुद्रा आय का हिस्सा 2021 में 1.38 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 1.58 प्रतिशत हो गया।

चार्ट XI.15: अंतरर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए) भारत की रैंकिंग में लगातार प्रगति

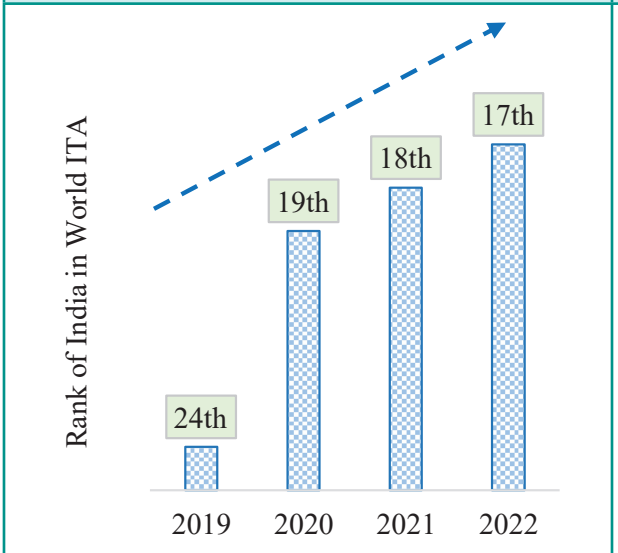

चार्ट XI.16: अंतरर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए) की लचीली बहाली

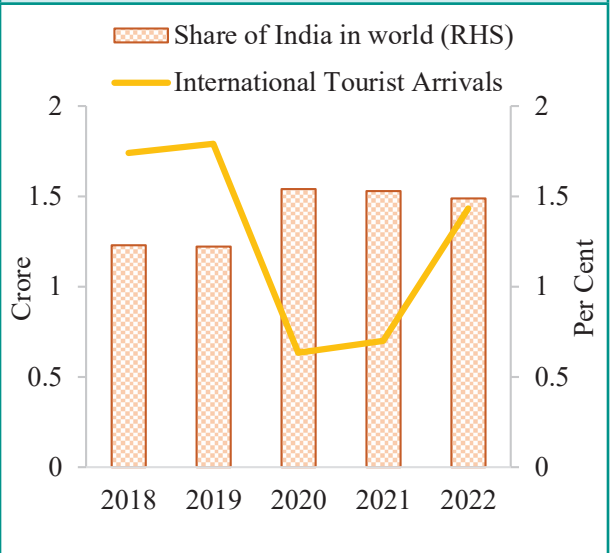

स्रोत: 2019 और 2020 के आंकड़े ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन स्रोत से लिए गए हैं। 2021 और 2022 के आंकड़े जनवरी 2024 के यूएनडब्ल्यूटीओ बैरोमीटर से लिए गए हैं।
नोट: (i) चार्ट XI.15 के लिए, 2021 और 2022 के मान अनंतिम हैं
(ii) चार्ट XI.16 के लिए, 2022 का मूल्य अनंतिम है।

18. पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 05 फरवरी 2024, नागर विमानन मंत्रालय। https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2002542
19. विश्व आर्थिक मंच (2024)। विश्व आर्थिक मंच यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024.। https://www3.weforum.org/docs/WEF_Travel_and_Tourism_Development_Index_2024.pdf
20. यूएनडब्ल्यूटीओ की परिभाषा के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए) में दो घटक शामिल हैं, अर्थात् विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) और अनिवासी नागरिकों का आगमन।

11.36 आतिथ्य उद्योग पर्यटकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और समग्र अतिथि अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ा है। वर्ष 2023 में, 14,000 अतिरिक्त कमरों के साथ सर्वाधिक संख्या में नई आपूर्ति की गई, जिससे भारत में श्रृंखला-संबद्ध कमरों की कुल सूची 183,000 हो गई।[21] होटल व्यवसायी अतिथि अनुभव को मूर्तरूप देने और परिचालन क्षमता में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी का तेजी से लाभ उठा रहे हैं। होटल भी नवोन्मेषी परिचालन रणनीतियाँ अपना रहे हैं, जैसे बाहरी रेस्तराँ, स्पा और लाउंज ब्रांड को पट्टे पर देना या प्रबंधित करना, ताकि होटल निवासियों को आकर्षित करने वाली स्थापित अवधारणाओं का लाभ उठाया जा सके, जिससे राजस्व में वृद्धि हो।[22] वित्त वर्ष 24 में, औसत दैनिक दर 6704 रूपये से बढ़कर 7616 रूपये हो गई, जो कि वर्ष-दर-वर्ष आधारित 13.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।[23]

11.37 भारत में पर्यटन के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं और कई सरकारी पहल इस क्षेत्र की प्रगति का समर्थन करती हैं। 'तीर्थयात्रा पुनर्नवीकरण और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान' (प्रसाद)[24] योजना के तहत पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए 29 नए स्थलों की पहचान की गई है और 12 का उद्घाटन किया गया है। स्वदेश दर्शन 2.0, एकीकृत पर्यटन गंतव्य विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 32 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 55 गंतव्यों को लक्षित करता है। भारत ने पहले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की अध्यक्षता की, जिसमें एससीओ सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोगी रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया। मंत्रालय ने पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 11वें अंतरर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट और भारत पर्व 2023 का आयोजन किया। इन प्रयासों के साथ-साथ सरकार ने पर्यटन उद्योग को समर्थन देने के लिए नीतिगत सुधारों और बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न उपायों को लागू किया है।

चार्ट XI.17: आतिथ्य सांख्यिकी

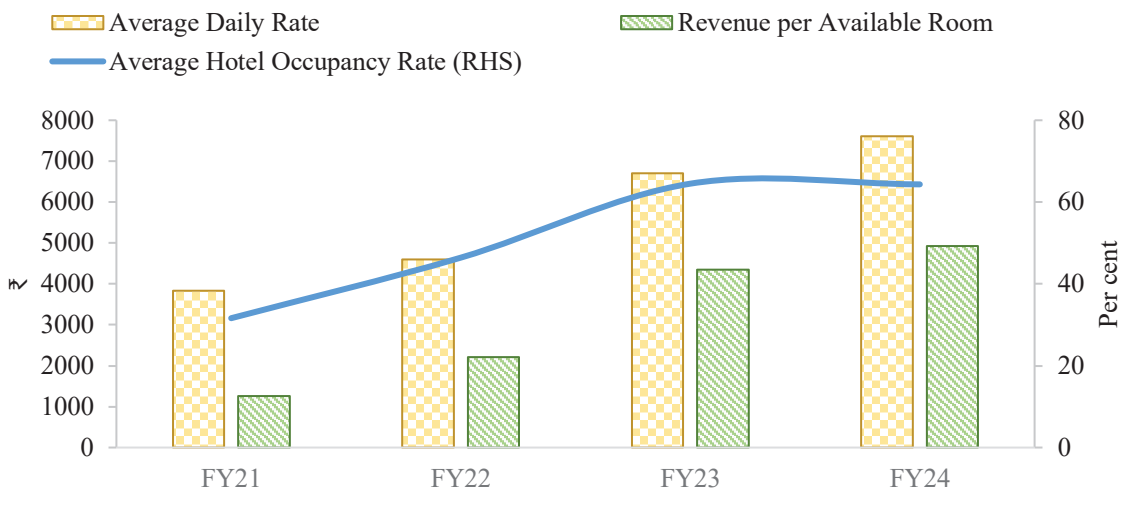

स्रोत[25] : एनारॉक - 'एचवीएस एनारॉक होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी ओवरव्यू' की मासिक रिपोर्ट से समेकित

21. होर्वाथ एच.टी.एल. (फरवरी 2024). भारत होटल बाजार समीक्षा रिपोर्ट 2023. https://horwathhtl.com/wp-content/uploads/sites/2/2024/02/India-Hotel-Market-Review-Report-2023.pdf

22. होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बेनोरी नॉलेज। विजन 2047: भारतीय होटल उद्योग। https://hotelassociationofindia.com/Vision%202047%20-%20March%2030.pdf

23. मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक एनारॉक (एचवीएस एनारॉक होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी ओवरव्यू) की मासिक रिपोर्टों से समेकित।

24. यह योजना धार्मिक पर्यटन के अनुभव को समृद्ध करने के लिए भारत भर में तीर्थ स्थलों को विकसित करने और उनकी पहचान करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य तीर्थ स्थलों को प्राथमिकता, योजनाबद्ध और टिकाऊ तरीके से एकीकृत करना है ताकि संपूर्ण धार्मिक पर्यटन का अनुभव प्रदान किया जा सके।

25. इसे अप्रैल 2020 से मार्च 2024 तक मासिक रिपोर्ट (एचवीएस एनारॉक होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी ओवरव्यू) का उपयोग करके समेकित किया गया है। वार्षिक औसत की गणना संबंधित महीनों की रिपोर्ट से मासिक डेटा का उपयोग करके की जाती है।

11.38 पर्यटन क्षेत्र ने डिजिटल क्रांति को अपनाया है। ऐसी ही एक पहल है ई-मार्केटप्लेस, जिसे वेब और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पर्यटकों और प्रमाणित पर्यटक सुविधा-दाताओं और मार्गदर्शकों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों के सहयोग से, राष्ट्रीय एकीकृत आतिथ्य उद्योग डेटाबेस (निधि) पोर्टल में देश भर में आवास इकाइयों को पंजीकृत करने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। यह डेटाबेस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नीतियों और कार्य-नीतियों को तैयार करने में सहायता करेगा। एक अन्य उल्लेखनीय पहल साथी (सिस्टम फॉर असेसमेंट, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री) है, जिसका उद्देश्य सरकारी कोविड नियमों पर आतिथ्य उद्योग को जागरूक करके वायरस के आगे के संचरण को रोकना है।

टेबल XI.1 : यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, 2024 में भारत की रैंकिंग 39 हुई

Enabling Environment					T&T Policy and Enabling Conditions			Infrastructure and Services			T&T Resources			T&T Sustainability		
Business Environment	Safety and Security	Health and Hygiene	Human Resources and Labour Market	ICT Readiness	Prioritisation of T&T	Openness to T&T	Price Competitiveness	Air Transport Infrastructure	Ground and Port Infrastructure	Tourist Services and Infrastructure	Natural Resources	Cultural Resources	Non-Leisure Resource	Environmental Sustainability	T&T Socioeconomic Impact	T&T Demand Sustainability
3.79	5.06	3.47	2.85	3.84	4.11	4.13	5.66	4.59	4.43	1.6	5.8	5.62	5.05	3.64	4.01	4.55

स्रोत: डब्ल्यूईएफ की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक (टीटीडीआई) 2024 रिपोर्ट[26]
नोट: टीएंडटी-यात्रा और पर्यटन

11.39 भारत का यात्रा एवं पर्यटन (टीएंडटी) क्षेत्र वैश्विक मुद्रास्फीति दबावों से प्रभावित रहा है और टीएंडटी क्षमता के सुधार में विलंब अन्य अर्थव्यवस्थाओं के समान है। हालांकि 2021 से कीमत प्रतिस्पर्धा में कमी अपने समकक्षों की तुलना में 0.7 प्रतिशत गिरावट के साथ न्यूनतम रही है। भारत की गिरावट 2021 में स्तरों से मात्र 0.1 प्रतिशत पर बहुत कम रही है जो कोविड-19 महामारी से आई मंदी के बावजूद स्थिरता बनाए रखने के सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। डब्ल्यूईएफ की टीटीडीआई, 2024 रिपोर्ट पर्यटन सेवाओं और अवसंरचना और कुशल कार्यबल के विकास में सुधार की आवश्यकता पर बल देती है। बढ़ते संरक्षणवाद, परिवहन लागत और आपूर्ति चिंताओं के कारण एआई के उदय और विनिर्माण के कारण सेवाओं में रोजगार सृजन के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल में, पर्यटन क्षेत्र रोजगार सृजन के लिए अपेक्षाकृत सुगमता से परिणाम प्रदान कर सकता है। भारत को इस अवसर का लाभ उठाना होगा। इस क्षेत्र में रोजगार को औपचारिक बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत पर्यटन सुविधाप्रदाता प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू किया है।[27] इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक डिजिटल मंच, जो आनलाइन लर्निंग के अवसर और प्रमाणन पाठ्यक्रम प्रदान कर सके, के माध्यम से राष्ट्रव्यापी पर्यटन सुविधाप्रदाताओं का एक कुशल संवर्ग सृजित करना है।[28]

26. विश्व आर्थिक मंच (मई 2024)। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक (टीटीडीआई) 2024. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Travel_and_Tourism_Development_Index_2024.pdf
तालिका में उल्लिखित 17 स्तंभों को दिए गए अंक कार्यकारी राय सर्वेक्षण (सर्वेक्षण) से प्राप्त आंकड़ों और अन्य स्रोतों से प्राप्त मात्रात्मक आंकड़ों के आधार पर गणना किए गए हैं। सर्वेक्षण डेटा का मान 1 (सबसे खराब) से 7 (सबसे अच्छा) तक होता है और मात्रात्मक डेटा संकेतकों को कार्यकारी राय सर्वेक्षण के परिणामों के साथ संरेखित करने के लिए 1 से 7 के पैमाने पर सामान्यीकृत किया जाता है।

27. वेबसाइट का लिंक - https://iitf.gov.in/

28. पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 21 जुलाई 2024, पर्यटन मंत्रालय। https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1843507

रियल एस्टेट

11.40 पिछले दशक में रियल एस्टेट और आवासों के स्वामित्व ने कुल जीवीए में सात प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया है, जो अर्थव्यवस्था में उनकी अभिन्न भूमिका को दर्शाता है। महामारी से प्रेरित लॉकडाउन और आर्थिक अस्थिरता के दो चुनौतीपूर्ण वर्षों के बाद, रियल एस्टेट क्षेत्र ने एक मजबूत रिकवरी का अनुभव किया है। महामारी ने घर खरीदने वालों की प्राथमिकताओं को अतिरिक्त सुविधाओं के साथ बड़े, टिकाऊ स्थानों की ओर स्थानांतरित कर दिया है, जो दूरस्थ और हाइब्रिड कार्य प्रवृत्तियों द्वारा संचालित है। इस बदलाव ने शहर के केंद्रों के करीब परिधीय क्षेत्रों में भी रुचि पैदा की है। इस सेक्टर के विकास में योगदान देने वाले कारकों में तेजी से शहरीकरण, आय के बढ़ते स्तर, एकल परिवारों का उदय, बाजार में नए प्रवेशकर्ता और डेवलपर्स और घर खरीदने वालों के लिए बेहतर वित्तीय विकल्प शामिल हैं। महामारी के दौरान घर के मालिक होने की प्रबल इच्छा को बल मिला, जिसने उत्प्रेरक का काम किया।

11.41 वर्ष 2023 में, भारत में आवासीय रियल एस्टेट की बिक्री 2013 के बाद से सबसे अधिक थी, जिसमें 33 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देखी गई, जिसमें शीर्ष आठ शहरों में कुल 4.1 लाख यूनिटों की बिक्री हुई। नई आपूर्ति ने अब तक का उच्चतम स्तर देखा, जिसमें 2023 में 5.2 लाख यूनिट लॉन्च किए गए, जबकि 2022 में 4.3 लाख यूनिट लॉन्च किए गए थे। वर्ष 2024 की पहली तिमाही में यही गति बनी रही, जिसमें 1.2 लाख यूनिट की रिकॉर्ड-तोड़ बिक्री देखी गई, जिसमें 41 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही से नई आपूर्ति लगातार एक लाख यूनिट से अधिक रही है, जो आवसन बाजार में निरंतर मांग-आपूर्ति की गतिशीलता को रेखांकित करती है।[29]

11.42 इसके अलावा, आवसन ऋण की बढ़ती मांग रियल एस्टेट की अंतर्निहित मांग को दर्शाती है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आवास ऋण वित्त वर्ष 12 से वित्त वर्ष 24 तक बढ़ा (चार्ट XI-18)। परंपरागत रूप से, आवसन वित्त क्षेत्र में सबसे बैंक महत्वपूर्ण घटक रहे हैं। हालांकि, आवसन वित्त कंपनियों (एचएफसी) ने पिछले कुछ वर्षों में इस परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने पिरामिड के निचले हिस्से में आवास ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों के साथ पूरक भूमिका निभाई। एचएफसी के कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में बकाया आवास ऋण की हिस्सेदारी 31 मार्च 2024 तक 70.8 प्रतिशत थी।

चार्ट XI.18: व्यक्तिगत गृह ऋण (आईएसएल) में वृद्धि

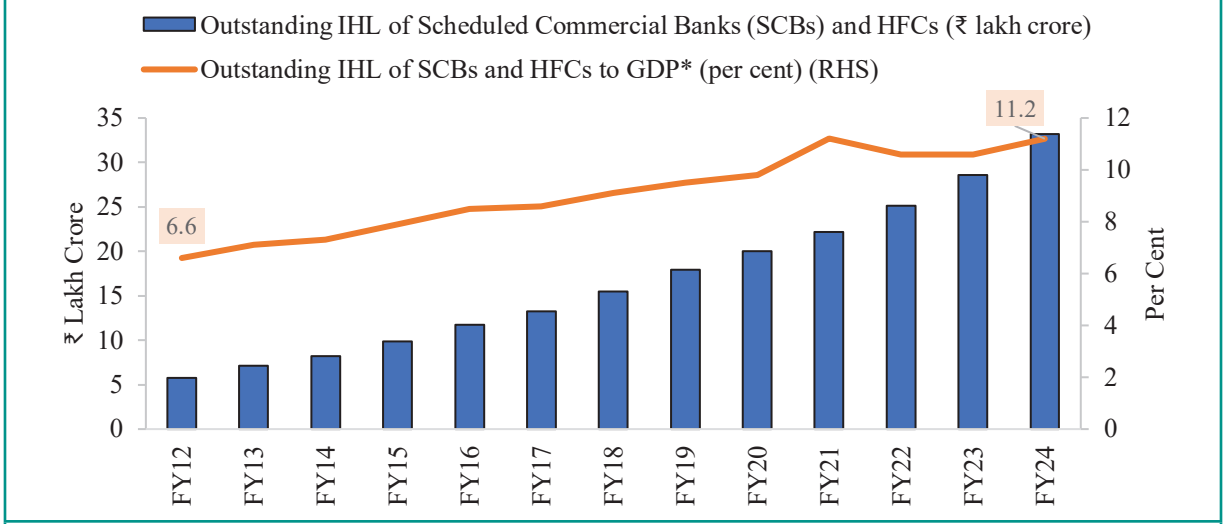

स्रोत: आरबीआई और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)
नोट: मौजूदा कीमतों पर जीडीपी पर विचार किया जाता है

29. प्रॉप टाइगर. (04 जनवरी 2024). 2023 में नए घरों की बिक्री में 33% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई: प्रॉपटाइगर.कॉम रिपोर्ट https://www.prop-tiger.com/guide/post/new-home-sales-record-33-yoy-growth-in-2023-proptiger-com-report

11.43 आवसन क्षेत्र की वृद्धि कई प्रमुख कारकों के कारण हुई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) ने शहरी लाभार्थियों के लिए 1.2 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी है, जिससे टिकाऊ आवासन सुनिश्चित हुआ है। माल एवं सेवा कर, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता जैसे नीतिगत सुधारों ने रियल एस्टेट में पारदर्शिता और निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है। किफायती आवास निधि और किफायती एवं मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो (एसडब्ल्यूएएमआईएच) निवेश निधि जैसी पहलों ने किफायती आवास परियोजनाओं का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम ब्याज अनुदान प्राथमिक मांग-पक्ष का प्रेरक रहा है, जिसमें राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने मार्च, 2024 तक 21.1 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित करने वाली सब्सिडी में ₹49,460.1 करोड़ जारी किए हैं। एचएफसी के साथ बैंक लिक्विडिटी को मिलाकर सह-उधार मॉडल का उद्देश्य कम आय वाले समूहों सहित व्यापक क्षेत्र में आवास ऋण का विस्तार करना है। एनएचबी द्वारा ₹10,000 करोड़ की प्रारंभिक निधि से प्रबंधित शहरी अवसंरचना विकास निधि ने शहरी अवसंरचना में सुधार किया है, तथा रियल एस्टेट में निवेश को आकर्षित किया है।

बॉक्स XI.2: विश्वास का निर्माण: रेरा किस प्रकार रियल एस्टेट को नया आकार दे रहा है

भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) को भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में बहुत जरूरी सुधार लाने के लिए अधिनियमित किया गया था। रेरा का मुख्य उद्देश्य अधिक पारदर्शिता, नागरिक-केंद्रितता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना है, जिससे घर खरीदारों को सशक्त बनाया जा सके और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित किया है, सिवाय नागालैंड जो नियमों को अधि सूचित करने की प्रक्रिया में है।

रेरा के कार्यान्वयन द्वारा प्रमुख उपाय और परिणाम

- **विकासकर्ता की जवाबदेही:** डेवलपर्स अक्सर वादा किए गए प्रोजेक्ट फीचर, लेआउट और सुविधाएं देने में विफल रहे, जिससे घर खरीदने वाले भ्रमित हो गए। रेरा अब पंजीकरण के समय 'बिक्री के लिए समझौता' अनिवार्य करता है और किसी भी लेआउट परिवर्तन के लिए आवंटियों/घर खरीदने वालों से दो-तिहाई सहमति की आवश्यकता होती है। दायित्व उल्लंघन के मामलों में रेरा सभी हितधारकों पर लागू होने वाले रिफंड, मुआवजे और दंड के प्रावधानों को भी निर्दिष्ट करता है।

- **निष्पक्ष लेनदेन:** रेरा लागू होने से पहले, ऐसे कई मामले सामने आए थे, जब बिल्डर्स घर खरीदारों से पूरा भुगतान करने के बावजूद फ्लैट या घर नहीं दे रहे थे। इस समस्या के समाधान के लिए, रेरा के अंतर्गत यह अनिवार्य किया गया है कि किसी परियोजना के लिए घर खरीदने वालों से एकत्रित धनराशि का 70 प्रतिशत, परियोजना निर्माण और भूमि लागत के लिए समर्पित एक अलग बैंक खाते में रखा जाना चाहिए।

- **प्रकटीकरण और अनिवार्य पंजीकरण:** रेरा ने डेवलपर्स और प्रोजेक्ट प्रमोटरों के लिए प्रोजेक्ट के बारे में सभी आवश्यक प्रकटीकरण करना भी अनिवार्य कर दिया है, जिसमें अधिकारियों से प्राप्त अनुमति, लॉन्च की तिथि, परिदान की वादा की गई तिथि, प्रोजेक्ट विशिष्टियां और सुख-सुविधाएँ शामिल हैं।[30] इसके अलावा, घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा की जाती है क्योंकि केवल रेरा के साथ पंजीकृत प्रोजेक्ट (500 वर्ग मीटर से ऊपर और आठ अपार्टमेंट से ऊपर) ही लॉन्च किए जा सकते हैं, जिससे डेवलपर्स द्वारा किसी भी तरह की गलत बयानी या झूठे वादों की संभावना समाप्त हो जाती है।[31] दिनांक 1 जुलाई 2024 तक, 1,30,186 से अधिक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और 88,461 रियल एस्टेट एजेंट रेरा के तहत पंजीकृत हो चुके हैं।

30. पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 12 अक्टूबर 2018, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx-?PRID=1549548

31. पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 01 नवंबर 2021, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/nov/doc202111121.pdf

- **विवाद समाधान:** रेरा विवादों के निपटारे के लिए फास्ट-ट्रैक विवाद समाधान तंत्र की स्थापना का प्रावधान करता है। 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की है, और 1 जुलाई 2024 तक 1,24,947 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है।

रेरा के लागू होने के बाद 2022 में ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत 36वें स्थान पर है।

11.44 रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए संभावनाएं उत्साहजनक हैं। बढ़ते शहरीकरण के साथ, आवसन उद्योग एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2050 तक भारत की आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी, जबकि 2011 में यह 31 प्रतिशत थी।[32] इससे आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा व्यवहार्य, लागत प्रभावी, टिकाऊ समाधान प्रदान करने के लिए रणनीतियों और नीतियों को अनुकूलित करने की आवश्यकता को बल मिलता है।

11.45 भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से भूमि लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी, संपत्ति के स्वामित्व संबंधी विवादों में कमी आएगी और भूमि प्रबंधन की दक्षता बढ़ेगी। निर्माण संबंधी मंजूरी के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली लागू करने से निर्माण प्रक्रियाओं में भी तेजी आएगी, जिससे विलंब और अनिश्चितताएं कम होंगी। मंजूरी को सरल बनाने से भारत के आवासीय रियल एस्टेट क्षेत्र के और अधिक समेकित और व्यवस्थित होने की उम्मीद है।

11.46 रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की विरासत एक चुनौती है। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के अनुमान के अनुसार, लगभग 4.1 लाख तनावग्रस्त आवासीय इकाइयाँ, जिनकी कीमत ₹4.1 लाख करोड़ है, प्रभावित हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने इस मुद्दे को हल करने के लिए रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समाधान सुझाने के लिए एक समिति की स्थापना की।[33] इस समिति ने दबाव के प्राथमिक कारण की पहचान वित्तीय व्यवहार्यता की कमी के रूप में की, जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि और देरी हुई। इसकी सिफारिशों में रेरा के साथ अनिवार्य परियोजना पंजीकरण, कब्जे वाली इकाइयों के लिए पंजीकरण/उप-पट्टा विलेखों का निष्पादन, काफी हद तक पूरी हो चुकी परियजनाओं का कब्जा सुनिश्चित करना, प्रमोटर के नेतृत्व वाले संकल्पों के लिए राज्य सरकार के पुनर्वास पैकेज का प्रस्ताव करना, रेरा और प्रशासक के नेतृत्व वाली परियोजना पुनरुद्धार के लिए रूपरेखा स्थापित करना, रुकी हुई परियोजनाओं को वित्तपोषित करना और परियोजनाओं के समाधान के लिए अंतिम उपाय के रूप में आईबीसी का उपयोग करना शामिल है। इनमें से कई सिफारिशें राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। एक पैकेज के रूप में उनके कार्यान्वयन से रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं के समाधान में मदद मिल सकती है।

11.47 क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में आवास ऋण बाजार वित्त वर्ष 2018 से वित्त वर्ष 23 तक लगभग 13 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा। इसके 13 से 15 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ते रहने की उम्मीद है, जो वित्तीय वर्ष 26 तक 42 लाख करोड़ रुपये से 44 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। एनएचबी ने वित्तपोषण विकल्पों की सीमाओं का समाधान करने के लिए एक आवासीय बंधक-समर्थित प्रतिभूति (आरएमबीएस) मंच पेश किया है। इस मंच का उद्देश्य पेंशन फंड और बीमा फंड सहित विविध निवेशक समूहों से दीर्घकालिक संसाधनों को आकर्षित करना है, ताकि आवास वित्त के विस्तार का समर्थन किया जा सके और प्राथमिक बंधकों के लिए ऋण बाजार को गहन बनाया जा सके। आरएमबीएस मंच ऋण देने वाली संस्थाओं के लिए परिसंपत्ति-देयता विषमताओं को कम करने में मदद करेगा, जिससे आवास वित्त क्षेत्र में पर्याप्त तरलता सुनिश्चित होगी।

---

32. संयुक्त राष्ट्र। (2018)। विश्व शहरीकरण परिप्रेक्ष्य: 2018 संशोधन - मुख्य बिंदु (पृष्ठ 23). https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Highlights.pdf

33. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। (जुलाई 2023)। विरासत में मिली रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए समिति की रिपोर्ट। https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/report(1).pdf

11.48 भविष्य में, आवास की मांग के वहनीयता और ऋण तक बढ़ती पहुंच से प्रेरित होने की उम्मीद है। बकाया व्यक्तिगत आवासन ऋणों में दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी राज्यों की हिस्सेदारी क्रमशः 35.4 प्रतिशत, 31.2 प्रतिशत और 26.2 प्रतिशत है। पूर्वी राज्यों में 6.9 प्रतिशत और आठ पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 0.95 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो पहुंच में सुधार के लिए पहल करने का अवसर प्रदान करती है।

11.49 वहनीयता और प्रौद्योगिकी रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अवरोधक के रूप में उभरे हैं। वहनीयता हरित निर्माण प्रथाओं और ऊर्जा-कुशल डिजाइनों को प्रभावित करेगी, जबकि प्रौद्योगिकी स्मार्ट घरों और डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि में क्रांति लाएगी। अधिक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सरोकारों के साथ, ऊर्जा-दक्ष प्रणालियों, वर्षा जल संचयन और स्मार्ट बिल्डिंग प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ, तकनीकी स्टार्ट-अप और वैश्विक क्षमता केंद्र

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाएँ

11.50 पिछले दशक में, सूचना और कंप्यूटर से संबंधित सेवाएं तेजी से महत्वपूर्ण हो गई हैं, कुल जीवीए में उनकी हिस्सेदारी वित्त वर्ष 13 में 3.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 5.9 प्रतिशत हो गई है। महामारी से प्रेरित आर्थिक मंदी के बावजूद, इस क्षेत्र ने वित्त वर्ष 21 में 10.4 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दर हासिल की। कोविड-19 महामारी ने प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों की उन्नति और तेजी को बढ़ावा दिया, जिससे इस क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा मिला। आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं ने निर्यात आय के माध्यम से देश के बाहरी संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो आगे और बढ़ने वाली है। आईटी सेवाओं के तेजी से विकास ने भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) और तकनीकी स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार में भी सहयोग दिया है।

वैश्विक क्षमता केंद्र

11.51 भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यह संख्या वित्त वर्ष 15 में 1,000 से अधिक केंद्रों से बढ़कर 1,580 से अधिक केंद्रों हो गए और वित्त वर्ष 23 तक 2,740 से अधिक इकाइयों तक हो गई। ये केंद्र उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार प्रदान करके आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। वित्त वर्ष 23 में, भारतीय जीसीसी में नियोजित कुल प्रतिभाएं 16.6 लाख से अधिक हो गईं। इस कार्यबल में से 42 प्रतिशत से अधिक इंजीनियरिंग, अनुसंधान और विकास (ईआरएंडडी), 34.5 प्रतिशत से अधिक व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन (बीपीएम) और 23.4 प्रतिशत आईटी सेवाओं में लगा हुआ है। सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र सामूहिक रूप से भारत की आईटी जीसीसी प्रतिभा का लगभग 58 प्रतिशत हिस्सा हैं। भारत के जीसीसी से राजस्व वित्त वर्ष 15 में 19.4 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 46 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है, जो 11.4 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है।

चार्ट XI.19: कार्यों के अनुसार जीसीसी के राजस्व का विभाजन (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

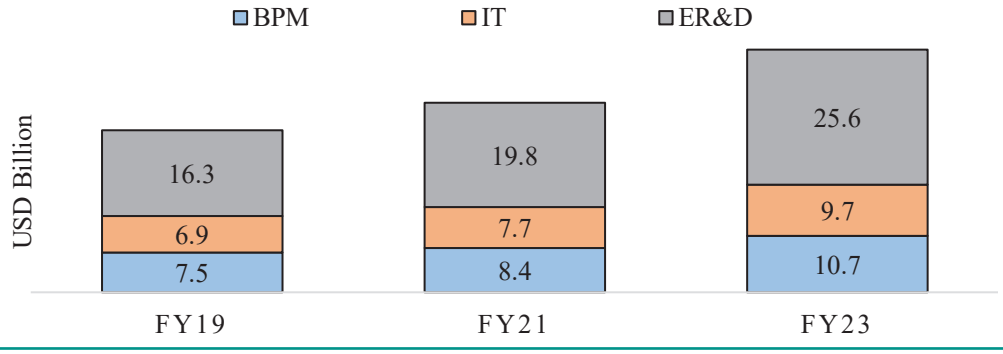

स्रोत: नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (**NASSCOM**)

11.52 नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) के अनुसार, भारत में ईआरएंडडी के विकास के लिए प्रमुख चालकों में रणनीतिक दीर्घकालिक साझेदारी, व्यापक डिजिटलीकरण और क्लाउड प्रौद्योगिकियों को अपनाना शामिल है। अनुप्रयोग आधुनिकीकरण, क्लाउड माइग्रेशन, प्लेटफॉर्म विकास और संबर्धित साइबर सुरक्षा उपायों की बढ़ती मांग के कारण आईटी सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ है। भारतीय जीसीसी में बीपीएम क्षेत्र पारंपरिक सेवाओं से अधिक बुद्धिमान संचालन और डेटा-संचालित समाधानों में व्यवस्था परिवर्तन करके विकसित हुआ है।

11.53 प्रौद्योगिकी क्षेत्र गतिशील हैं और लगातार विकसित हो रहे हैं, जिससे वे कर्मचारियों और व्यवसायों के लिए आकर्षक बन गए हैं। वैश्विक नौकरी बाजार में आईटी पद सबसे अधिक मांग वाली भूमिकाओं में से एक हैं। उच्च मांग के बावजूद, इन क्षेत्रों में आईटी, डेटा विज्ञान और साइबर सुरक्षा कर्मचारियों की कमी के साथ प्रतिभा की कमी का सामना करना पड़ रहा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार[34], 2024 की तीसरी तिमाही के लिए, 76 प्रतिशत आईटी नियोक्ताओं ने वैश्विक स्तर पर आवश्यक कुशल प्रतिभाओं को खोजने में कठिनाई की सूचना दी। भारत में जीसीसी को प्रोत्साहित करने के लिए, उच्च शिक्षा में विशेषज्ञता को बढ़ावा देना आवश्यक है। फोकस क्षेत्रों में ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबरसिक्यूरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, 3डी प्रिंटिंग और वेब और मोबाइल डेवलपमेंट शामिल होने चाहिए।

11.54 प्रतिभा की कमी को दूर करने के लिए कई पहल की गई हैं। अपनी तरह की पहली पहल के रूप में परिकल्पित 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम', जो कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटीवाई) और नेस्कॉम की एक संयुक्त पहल है, का उद्देश्य आईटी पेशेवरों की अभिरूचियों और योग्यता के अनुरूप उनके कौशल में निरंतर वृद्धि की सुविधा के लिए फोकस क्षेत्रों में अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग इकोसिस्टम बनाना है।[35] सरकार ने उभरती और भविष्य की तकनीकों में डिजिटल कौशल कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका लक्ष्य इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और रोजगार के अवसरों के माध्यम से एक करोड़ छात्रों को कौशल, पुन: कौशल और कौशल उन्नयन प्रदान करना है।[36] प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 4.0) युवाओं के बीच कौशल

34. मैनपावरग्रुप (2024)। वैश्विक रोजगार परिदृश्य: तीसरी तिमाही 2024. https://go.manpowergroup.com/hubfs/GLOBAL_EN_MEOS_Report_3Q24.pdf

मैनपावरग्रुप रोजगार परिदृश्य सर्वेक्षण एक अग्रगामी रोजगार सर्वेक्षण है जिसका उपयोग वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख आर्थिक संकेतक के रूप में किया जाता है। यह सर्वेक्षण 42 देशों और क्षेत्रों में 40,374 सार्वजनिक और निजी नियोक्ताओं के साक्षात्कारों पर आधारित है, ताकि प्रत्येक तिमाही में प्रत्याशित रोजगार प्रवृत्तियों को मापा जा सके। https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Highlights.pdf

35. पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 29 अक्टूबर 2021, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx-?PRID=1767604

36. शिक्षा मंत्रालय की दिनांक 06 जून 2022 की पीआईबी विज्ञप्ति। https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1831624

विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, जो उद्योग 4.0[37], एआई, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन[38] जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करती है।

भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप

11.55 कोविड-19 महामारी ने उपभोक्ता और उद्यम की प्रौद्योगिकी समर्थित समाधानों की मांग को बढ़ावा दिया है। भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप की संख्या 2014 में लगभग 2,000 से बढ़कर 2023 में लगभग 31,000 हो गई है। नैसकॉम के अनुसार, इस क्षेत्र में 2023 में लगभग 1000 नए टेक स्टार्ट-अप्स की शुरुआत हुई है।

11.56 वर्ष 2023 में स्टार्ट-अप के लिए शीर्ष क्षेत्र एडटेक (16 प्रतिशत), एंटरप्राइजटेक (12 प्रतिशत), बीएफएसआई (10 प्रतिशत), विज्ञापन और विपणन (7 प्रतिशत), रिटेलटेक (6 प्रतिशत), मीडिया और मनोरंजन (5 प्रतिशत), कंज्यूमरटेक (5 प्रतिशत), पेशेवर सेवाएं (4 प्रतिशत) और गेमिंग (4 प्रतिशत) थे।

11.57 विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्ट-अप के उदय में कई कारकों ने योगदान दिया है। उपभोग पैटर्न में बदलाव और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच ने रिटेल टेक स्टार्ट-अप के लिए रास्ता तैयार किया। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की शुरूआत जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण 2016 से बीएफएसआई क्षेत्र में स्टार्ट-अप में उछाल देखा गया। स्केलेबल और कुशल क्लाउड समाधानों की मांग ने 'सॉफ्टवेयर ऐज अ सर्विस' (एसएएएस) स्टार्ट-अप के विकास को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप 2014 से 21 यूनिकॉर्न बने। कोविड-19 महामारी ने हेल्थटेक और एडटेक जैसे क्षेत्रों में विकास को गति दी, जो टेली-कंसल्टिंग और रिमोट लर्निंग समाधानों की बढ़ती जरूरत से प्रेरित था।

11.58 नैसकॉम के अनुसार, भारत का टेक स्टार्ट-अप इकोसिस्टम विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है और इसने अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है।[39] भारतीय टेक स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की ताकत इसके स्टार्ट-अप, यूनिकॉर्न और मापने की क्षमता में निहित है। विश्व की 16 प्रतिशत एआई प्रतिभा के साथ, भारत स्वयं को एक नवाचार हब के रूप में स्थापित करता है, जो एआई कौशल को तेजी से अपना रहा है।

11.59 भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों में स्टार्ट-अप इंडिया पहल और स्टार्ट-अप हब ने टेक स्टार्ट-अप के विकास में सहायता की है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलों में राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्ट-अप नीति, ड्रोन शक्ति कार्यक्रम और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) से संबंधित पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के लिए सीमा शुल्क छूट शामिल हैं। इस स्टार्ट-अप क्षमता का और अधिक दोहन करने के लिए किए गए लक्षित प्रयासों का विवरण नीचे दिया गया है।

- **डीप-टेक इकोसिस्टम को गति देना और मजबूत करना:** 31 मार्च 2024 तक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में 1.25 लाख से अधिक डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप हैं, जिनमें से 13,000 से अधिक स्टार्ट-अप ऐसे हैं जो एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स एंड नैनोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्ट-अप नीति (एनडीटीएसपी)[40] का मसौदा डीप टेक स्टार्ट-अप की चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। यह नीति सीमित वित्तपोषण, संसाधन और बुनियादी ढाँचे की कमी जैसी महत्वपूर्ण बाधाओं का समाधान करती है और अत्याधुनिक तकनीकों से जुड़े जोखिमों को समझती है। यह वित्तपोषण तंत्र को डिजाइन करके हस्तक्षेप करती है जो 'डिजाइन द्वारा विफल' की अवधारणा को अपनाता है, स्टार्ट-अप संस्थापकों के लिए अपने वित्तपोषण के स्रोतों

37. उद्योग 4.0 एक शब्द है जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में स्वचालन, अंतसंयोजनीयता और डेटा विनिमय की वर्तमान प्रवृत्ति को दिया गया है।

38. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की दिनांक 26 दिसंबर 2023 की पीआईबी विज्ञप्ति। https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx-?PRID=1990495

39. नैसकॉम और जिनोव (2023)। चुनौतियों का सामना करना - भारतीय टेक स्टार्ट-अप परिदृश्य रिपोर्ट 2023. https://www.nasscom.in/knowledge-center/publications/weathering-challenges-indian-tech-start-landscape-report-2023

40. ड्राफ्ट नेशनल डीप टेक स्टार्ट-अप पॉलिसी 2023 (पेज 3). https://psa.gov.in/CMS/web/sites/default/files/process/NDTSP.pdf

में विविधता लाने के लिए वित्तपोषण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है, अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बौद्धिक संपदा संरक्षण की सुविधा के लिए एक केंद्रीकृत प्रमुख मिशन कार्यालय की स्थापना करता है, टियर 2 और 3 शहरों में जागरूकता बढ़ाता है, और प्रमुख निष्पादन संकेतकों की मैपिंग के आधार पर एक निगरानी तंत्र अभिकल्पित करता है।

चार्ट XI.20: भारत के टेक स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में डीपटेक का उपयोग मुख्यधारा में आ रहा है

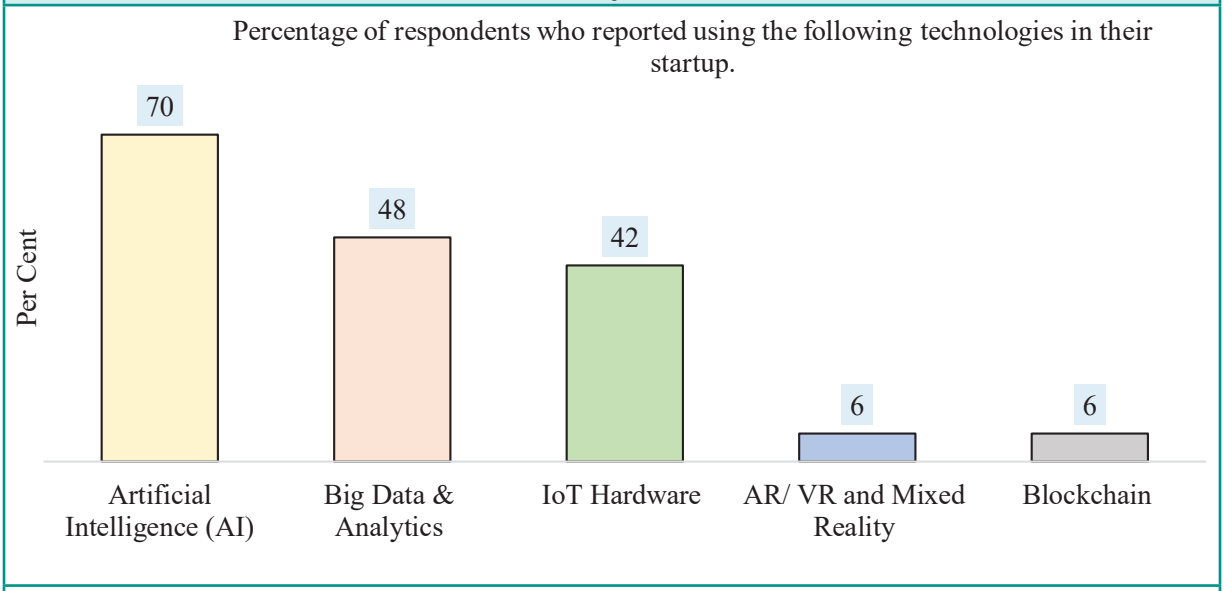

स्रोत: टेक स्टार्ट-अप सर्वेक्षण 2023, नैसकॉम और जिनोव रिपोर्ट - चुनौतियों का सामना - भारतीय टेक स्टार्ट-अप परिदृश्य रिपोर्ट 2023
नोट: (i) कुल प्रतिशत 100 से अधिक है क्योंकि उत्तरदाता विविध विकल्प चुन सकते हैं।
(ii) आईओटी-इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआर-ऑगमेंटेड रियलिटी, वीआर-वर्चुअल रियलिटी

- **घरेलू पूंजी प्रवाह को मजबूत करना:** सरकार ने स्टार्ट-अप की वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रूपये के कोष के साथ स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की है। इसने न केवल शुरुआती चरण, बीज चरण और विकास चरण में स्टार्ट-अप के लिए पूंजी उपलब्ध कराई है, बल्कि घरेलू पूंजी जुटाने, विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम करने और घरेलू और नए उद्यम पूंजी कोष को प्रोत्साहित करने में भी उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। उद्यम विकास के लिए प्रारंभिक चरण के समर्थन के महत्व को पहचानते हुए, 2021 में शुरू की गई स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम का उद्देश्य अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्ट-अप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।[41]

- **स्टार्ट-अप इंडिया जैसी पहलों का लाभ उठाना:** स्टार्ट-अप इंडिया पहल भारतीय स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने में मदद करती है। स्टार्ट-अप इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय ज्ञान विनिमय प्रणाली बनाने और सीमा-पार ऊष्मायन और त्वरण कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों में भाग लिया है।[42]

41. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, दिनांक 29 मार्च, 2023 की पीआईबी विज्ञप्ति। https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx-?PRID=1911913

42. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)। राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग 2022 (पृष्ठ 25) https://www.startupindia.gov.in/srf-2022/SRF_2022_Result_page/National_Report_14_01_2024.pdf

दूरसंचार

11.60 दूरसंचार भारत में डिजिटल सेवाओं के तेज विकास का प्रवेश द्वार है। भारत में कुल टेलीघनत्व (प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोन की संख्या) मार्च, 2014 में 75.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2024 में 85.7 प्रतिशत हो गया।[43] मार्च, 2024 के अंत में वायरलेस टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 116.5 करोड़ थी। सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के अंग के रूप में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड के विकास पर काफी जोर दिया है। परिणामस्वरूप, इंटरनेट ग्राहकों की संख्या मार्च, 2014 में 25.1 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2024 में 95.4 करोड़ हो गई, जिनमें से 91.4 करोड़ वायरलेस फोन के जरिए इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। मार्च, 2024 में इंटरनेट घनत्व भी बढ़कर 68.2 प्रतिशत हो गया। डेटा की लागत में काफी कमी आई है, जिससे प्रति ग्राहक औसत वायरलेस डेटा उपयोग में काफी सुधार हुआ है।

11.61 भारत में 5जी सेवाएँ पहली बार अक्टूबर, 2022 में शुरू की गई थीं। वर्तमान में, भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते 5जी नेटवर्कों में से एक है। 5जी सेवाओं के प्रारंभ के बाद, मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंक 118 से बढ़कर 15 (मार्च, 2024) हो गई है। यह '5जी टेस्ट बेड', जिसे 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया, एक एंड-टू-एंड परीक्षण सुविधा प्रदान करता है, जिससे भारतीय शिक्षा और उद्योग में अनुसंधान एवं विकास समूहों को अपने उत्पादों, प्रोटोटाइप और एल्गोरिदम को मान्य करने और विभिन्न सेवाओं का प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। भारत 5जी पोर्टल भारत की 5जी क्षमताओं को बढ़ावा देता है और दूरसंचार क्षेत्र के भीतर नवाचार, सहयोग और ज्ञान-साझाकरण को बढ़ावा देता है।

11.62 6जी पर प्रौद्योगिकी नवाचार समूह की सिफारिशों के आधार पर, भारत में 6जी नेटवर्क प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और उपयोजित करने के लिए मार्च, 2023 में भारत 6जी विजन दस्तावेज लॉन्च किया गया था। इसके फलस्वरूप 6जी मिशन के चरण-वार उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए भारत 6जी मिशन और एक शीर्ष परिषद का गठन भी किया गया। जुलाई, 2023 में भारत 6जी गठबंधन भी सार्वजनिक और निजी कंपनियों, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों और मानक विकास संगठनों के एक सहयोगी मंच के रूप में लॉन्च किया गया था ताकि भारत को किफायती 5जी और 6जी और भविष्य के अन्य दूरसंचार समाधानों के आईपी, उत्पादों और समाधानों का एक अग्रणी वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने में सक्षम बनाया जा सके।

11.63 देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए संशोधित भारत नेट प्रोग्राम की शुरुआत की जाती है। 31 मार्च, 2024 तक 6,83,175 किलोमीटर तक ऑप्टीकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछा दिए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप भारत नेट चरण-I और II में ओएफसी द्वारा कुल 2,06,709 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है।

11.64 सरकार ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर विनियामक बोझ को कम करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कई संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधार भी लागू किए हैं। इनमें समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा को तर्कसंगत बनाना, स्पेक्ट्रम से संबंधित सुधार जैसे स्पेक्ट्रम को साझा करने और व्यापार करने की अनुमति देना और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क को तर्कसंगत बनाना, सुरक्षा उपायों के अधीन स्वचालित मार्ग के तहत दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना आदि शामिल हैं। दूरसंचार अधिनियम, 2023 दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क, स्पेक्ट्रम के आवंटन आदि से संबंधित कानूनों को संशोधित और समेकित करता है।

11.65 दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास तथा व्यावसायीकरण के लिए व्यापक और अध्यवसायी पूंजी की आवश्यकता होती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार ने निर्णय लिया है कि दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के वित्तपोषण के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)[44] से वार्षिक संग्रहण का 5

43. प्रेस विज्ञप्ति संख्या 36 दिनांक 04 जुलाई 2024। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण https://www.trai.gov.in/sites/default/files/PR_No.36of2024.pdf

44. सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) का उद्देश्य देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और किफायती मोबाइल और डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है, जिससे मोबाइल और नेटवर्क सेवाओं तक गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच के साथ-साथ ज्ञान और सूचना प्रसार तक समान पहुंच हो सके, जिससे जीवन स्तर में सुधार के साथ तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके।

प्रतिशत आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2022 में तैयार किए गए दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष में स्टार्ट-अप, एमएसएमई, शिक्षाविदों और उद्योग की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई है।

11.66 इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में इंजीनियरिंग कार्यक्रमों को उद्योग में उभरती जरूरतों के साथ जोड़ने के लिए नए पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया गया है। 5जी और 5जी-सक्षम प्रौद्योगिकी से संबंधित कौशल पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा अनुमोदित किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने संकाय विकास कार्यक्रम के लिए एआईसीटीई प्रशिक्षण और शिक्षण अकादमी योजना में 5जी को एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में शामिल किया है।

11.67 मई, 2023 में शुरू किया गया संचार साथी पोर्टल[45], मोबाइल ग्राहकों को सशक्त बनाने, उनकी सुरक्षा को सुदृढ़ करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नागरिक-केंद्रित पहल है। संचार साथी पोर्टल में कई घटक हैं, जिनमें मार्च, 2024 में शुरू की गई चक्षु सुविधा भी शामिल है, जिसका उपयोग संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। प्राप्त शिकायतों के आधार पर उचित कार्रवाई की जा रही है।

ई-कॉमर्स

11.68 भारतीय ई-कामर्स उद्योग के 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर पार करने की संभावना है। भारतीय खुदरा बाजार काफी हद तक असंगठित है। हालाँकि, अगले 3 से 5 वर्षों में आधुनिक खुदरा (ई-कॉमर्स सहित) की हिस्सेदारी कुल खुदरा बाजार में 30-35 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।[46]

11.69 तकनीकी प्रगति, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, यूपीआई, एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल, डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क (ओएनडीसी), नई विदेश व्यापार नीति, एफडीआई सीमा में छूट और उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियम 2021 जैसी सरकारी पहलों के साथ-साथ विकसित हो रहे नए जमाने के व्यापार मॉडल के कारण भारत के ई-कॉमर्स बाजार ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है। ई-कॉमर्स के तेजी से विस्तार के केंद्र में पारंपरिक ब्रिक-और-मोर्टार बाजारों की तुलना में ई-मार्केटप्लेस द्वारा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को प्रदान किए जाने वाले लाभों की विविधता है।

11.70 ऑनलाइन बिक्री के लिए आवश्यक कौशल की अपर्याप्तता, जैसे कैटलॉगिंग, के कारण ई-कॉमर्स का उदय बाधित है। डेटा गोपनीयता के मुद्दे और ऑनलाइन धोखाधड़ी में वृद्धि भारत में ई-कॉमर्स के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन गई है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग के बारे में उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करना अनिवार्य हो जाता है। शुरुआत के लिए, सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कई पहलों को लागू किया है। प्रमुख विनियमों में ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं से उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 शामिल हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 एक व्यापक डेटा संरक्षण ढांचा प्रदान करता है, जो उपभोक्ता जानकारी को और अधिक सुरक्षित बनाता है।

11.71 जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार जागो-ग्राहक-जागो अभियान चलाती है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और सुरक्षित ई-कॉमर्स प्रथाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच)

45. वेबसाइट का लिंक- https://sancharsaathi.gov.in/

46. इन्वेस्ट इंडिया. ई-कॉमर्स: दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता ई-कॉमर्स बाजार। https://www.investindia.gov.in/sector/retail-e-commerce

मार्गदर्शन प्रदान करती है और उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करती है।[47] डिजिटल साक्षरता कार्यशालाओं और साइबर सुरक्षा सत्रों सहित विभिन्न उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ इंटरैक्टिव सत्र और वेबिनार उपभोक्ताओं को ई-कॉमर्स क्षेत्र में नवीनतम रुझानों और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरुक रखते हैं।

11.72 भारत में खरीदार पारिस्थितिकी-तंत्र बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, और सेवा अपेक्षाओं, मूल्य संवेदनशीलता और भाषा आवश्यकताओं के संबंध में विविध दुकानदारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यवसाय मॉडल में नवाचार की आवश्यकता होगी। स्थानीय भाषा प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है क्योंकि दुकानदारों का आधार टियर-2 और टियर-3 शहरों तक फैल रहा है। बढ़ते स्टार्ट-अप और नवोन्मेषी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अद्वितीय व्यवसाय मॉडल की परख करने का अवसर प्रदान करते हैं जिन्हें विशिष्ट जनसांख्यिकीय समूहों को लक्षित किया जा सकता है।[48] ई-कॉमर्स का भविष्य एआई, सहज डिजिटल भुगतान विधियों, यूपीआई जैसे नवाचारों और व्यवसाय संचालन और संवर्द्धन के लिए व्यवसाय इंजीनियरिंग डेटा विश्लेषिकी के माध्यम से बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव पर आधारित है। इसके अलावा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) जैसे प्लेटफॉर्म ई-कॉमर्स क्षमताओं की पहुँच बढ़ाते हैं।

बॉक्स XI.3: ओएनडीसी - डिजिटल वाणिज्य का लोकतंत्रीकरण

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक अग्रणी पहल है, जिसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना और छोटे व्यवसायों को समान अवसर प्रदान करके डिजिटल कॉमर्स के लाभों का फायदा उठाने में सक्षम बनाना है। ओएनडीसी नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के विभिन्न घटकों को अलग-अलग करने और उन्हें आपस में जोड़ने के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। ओएनडीसी की शुरुआत जनवरी, 2022 में हुई और इसने गतिशीलता और खाद्य एवं पेय पदार्थों के अपने दोहरे डोमेन को किराना, फैशन, सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल, घर और रसोई, ऑन-नेटवर्क लॉजिस्टिक्स, कृषि, उपहार कार्ड, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और कारीगरी के कामों जैसे विभिन्न डोमेन में तेजी से विस्तार किया।

ओएनडीसी का विकास मानचित्र

68 million Transactions since inception	**1200+** Cities	**65** Seller Applications	**12** Logistic Service Providers
85% Small sellers	**535,000+** Sellers	**9** million Transactions per month	**22** Buyer Applications

प्रमुख डोमेनों की अद्यतन स्थिति

- **खाद्य और पेय:** यह नेटवर्क रेस्टोरेंट भागीदारों को लागत प्रभावी लाभ प्रदान करता है, जिससे प्रमुख एग्रीगेटर्स द्वारा लगाए जाने वाले उच्च शुल्क का बोझ कम होता है। वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही के दौरान, 347 शहरों में सेवा देने वाले 95,000 से अधिक रेस्टोरेंट और शीर्ष ब्रांडों के मजबूत नेटवर्क के कारण ऑर्डर में 18 प्रतिशत

47. पीआईबी विज्ञप्ति, दिनांक 06 दिसंबर 2023, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1983226

48. बैन एंड कंपनी. (13 दिसंबर 2023). हाउ इंडिया शॉप्स ऑनलाइन 2023 https://www.bain.com/insights/how-india-shops-online-2023/#

की वृद्धि हुई। टाटा न्यू, डोमिनोज और ओला जैसे बड़े ब्रांड नामों ने अपने ऐप में खाद्य सेवाएँ जोड़ी हैं, जबकि मैजिकपिन और पेटीएम जैसे अन्य प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और विशेष सौदों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह नेटवर्क दिल्ली-एनसीआर और लखनऊ में 350 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षित करके अपनी पहुँच का विस्तार कर रहा है।

- **किराना:** वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में, किराना ऑर्डर में 52 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की गई, जिसे 665 से अधिक शहरों में 12,585 विक्रेताओं के नेटवर्क द्वारा सुगम बनाया गया। पेटीएम और ओटिपी जैसे प्रमुख ब्रांड उन्नत डिजिटल स्टोरफ्रंट और क्यूआर कोड तकनीक में निवेश कर रहे हैं। कैच जैसे ब्रांडों के साथ सहयोग से उत्पाद की पेशकश में वृद्धि हो रही है, जिसमें वर्तमान में 6.3 मिलियन स्टॉक-कीपिंग यूनिट (एसकेयू) शामिल हैं। किको लाइव जैसी पहल स्थानीय किराना स्टोरों को सक्रिय रूप से डिजिटल बना रही है, जिसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और आईटीसी जैसी प्रमुख कंपनियों का समर्थन प्राप्त है, जो ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर 1.3 मिलियन किराना स्टोरों को डिजिटल बनाने की रणनीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं।

- **फैशन, सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल:** वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में 6400 से अधिक विक्रेताओं के समर्थन से 11 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो लगभग 900 शहरों में 15 लाख से अधिक एसकेयू की व्यापक पसंद पेश करते हैं। तिमाही के दौरान, जॉकी, कल्याण सिल्क, बेला वीटा और इमामी ब्यूटी जैसे प्रमुख ब्रांड नेटवर्क में शामिल हुए।

- **कृषि:** ओएनडीसी नेटवर्क किसानों और कारीगरों की आजीविका में काफी सुधार लाने की संभावना रखता है। अब तक लगभग 5,700 एफपीओ इस नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं, और उन्होंने वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही के दौरान सामूहिक रूप से 23,000 से अधिक लेन-देन किए हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) और लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के डिजिटल अनुप्रयोगों को भी नेटवर्क में एकीकृत किया गया है।

डिजिटल रूप से सशक्त समावेशी कहानियां

- तमिलनाडु के कांचीपुरम में श्री विद्या हैंडलूम्स ने ओएनडीसी के माध्यम से डिजिटल कॉमर्स में बदलाव किया। इस पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसाय ने अपनी पहुंच 54 शहरों तक बढ़ाई और अपनी उत्पाद लिस्टिंग को 20 से 400 डिजिटल कैटलॉग तक बढ़ाया। मुख्यधारा के प्लेटफॉर्म पर 10,000 रूपये से 20,000 रूपये की पिछली आय की तुलना में मासिक राजस्व बढ़कर लगभग 2 लाख रूपये हो गया। ओएनडीसी पर कमीशन की कम दरों ने लाभप्रदता को बढ़ाया।

- ओएनडीसी ने मन देशी फाउंडेशन और कुदुम्बश्री सहित 76 स्वयं सहायता समूहों की दस लाख से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाया है, जिससे 1,200 से अधिक ऑर्डर पूरे हुए हैं। नवोन्मेषी विपणन और टिकाऊ प्रथाओं ने ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दिया है। औसत ऑर्डर वॉल्यूम और राजस्व मार्जिन में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- महाराष्ट्र में कल्पनिल नेचुरल्स कोल्ड-प्रेस्ड तेलों का उत्पादन करता है और अप्रैल, 2023 में ओएनडीसी में एकीकृत हो गया। 13 एसकेयू सूचीबद्ध होने के साथ, ब्रांड का विस्तार 44 शहरों में हुआ और सितंबर, 2023 तक 2.5 लाख रुपये का राजस्व सृजित किया। संस्थापक ने बिचौलियों को हटा कर लाभ मार्जिन को बढ़ाने और व्यापार वृद्धि को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में ओएनडीसी की भूमिका पर जोर दिया।

- नम्मा यात्री, एक सवारी-उठाने (राइड हेलिंग) वाला मंच जो ओएनडीसी के साथ एकीकृत है, कमीशन को समाप्त करता है और सदस्यता शुल्क पर काम करता है। बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा चालक संघ के सहयोग से शुरू की गई इस योजना ने चालकों की आय में वृद्धि की और कैंसिलेशन दरों में कमी की।

चुनौतियाँ और अवसर

11.73 यह खंड विभिन्न सेवा क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों और विकास के अवसरों का सारांश प्रस्तुत करता है, जिन्हें ऊपर विभिन्न खंडों में प्रस्तुत किया गया है।

- सेवा क्षेत्र में तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण के कारण तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कुशल कार्यबल की आवश्यकता है। हालांकि, प्रासंगिक डिजिटल और उच्च तकनीक कौशल वाले श्रमिकों की उपलब्ध ता में कमी है। सरकार कौशल भारत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास पहलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि कार्यबल को आवश्यक कौशल से लैस किया जा सके। उद्योग के सहयोग से सरकारी पहलों द्वारा प्रोत्साहित किए गए पारिस्थितिकी-तंत्र के माध्यम से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौशल विकास से भारत को साइबर सुरक्षा, उद्यम प्रबंधन, वित्तीय जोखिम प्रबंधन और बीमा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले उच्च-मान वाले भागीदार के रूप में उभरने में मदद मिल सकती है।
- आर्थिक गतिविधि के लिए संभार-तंत्र और परिवहन सेवाओं के महत्व को पहचानते हुए, बुनियादी ढांचे की बाधाओं, संभार-तंत्र लागत और विनियामक अनुपालन को कम करने के लिए कई पहल की गई हैं। इसके अतिरिक्त, बंदरगाह संचालन और अंतर्देशीय जलमार्ग जैसी उन्नत सेवाओं के लिए भारत की व्यापक तटरेखा और नदी नेटवर्क का लाभ उठाने से परिवहन मार्गों को सुव्यवस्थित करने, लागत कम करने और दक्षता में सुधार करने की महत्वपूर्ण क्षमता हासिल होने की आशा है। नीदरलैंड में यूरोप के अंतर्देशीय जलमार्गों का सबसे घना नेटवर्क है, जो लगभग 6,000 किलोमीटर की नदियों और नहरों को कवर करता है। ये जलमार्ग जल निकासी और नेविगेशन सहित विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। कुल 2,200 किलोमीटर के, प्रमुख वाणिज्यिक मार्ग (श्रेणी IV और उच्चतर), अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई का लगभग 40 प्रतिशत और देश के भीतर घरेलू माल ढुलाई का 20 प्रतिशत संभालते हैं।[49] केरल द्वारा कोच्चि जल मेट्रो पर्यटन, वाणिज्य और परिवहन के लिए अपने बैकवाटर का सफल उपयोग करने से 33,000 द्वीपवासियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता को रेखांकित करता है।[50] देश भर में इसी प्रकार की रणनीति अपनाने से भारत की अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली को बढ़ावा मिल सकता है, सतत विकास को बढ़ावा मिल सकता है तथा भीड़भाड़ कम हो सकती है।
- विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में कार्यरत लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए वित्त तक पहुंच बनाना कठिनाइयां पैदा कर सकता है।[51] ऋण सुलभता को आसान बनाने के लिए मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी कई पहलों को लागू किया गया है। इन प्रयासों के आधार पर, ऋण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, ऋण गारंटी योजनाओं की पहुँच बढ़ाने, वैकल्पिक ऋण मूल्यांकन विधियों को अपनाने और आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण में नवाचार लाने पर ध्यान केंद्रित करके इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह को और बढ़ाया जा सकता है। सरकार उचित स्तरों पर परियोजना दस्तावेजीकरण में सहायता करने तथा परियोजनाओं की बैंकिंग क्षमता में सुधार करने के लिए एजेंसियां भी स्थापित कर सकती हैं।
- सेवा क्षेत्र में विनियामक परिदृश्य, जो पहले जटिल हुआ करता था, सकारात्मक परिवर्तनों से गुजर रहा है। जीएसटी सरलीकरण, स्टार्ट-अप इंडिया और भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम जैसी क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों जैसी पहलों से और अधिक अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा मिल रहा है। एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से प्रक्रियाओं के सरलीकरण को और बढ़ाना, कानूनी प्रावधानों को सुव्यवस्थित करना और सभी प्रशासनिक स्तरों पर सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना आर्थिक दक्षता को काफी हद तक बढ़ा सकता है।

---

49. विश्व की नहरें। नीदरलैंड, 30 जून 2024 को को निम्नलिखित लिंक से प्राप्त: http://worldcanals.org/english/netherlands.html#:~:text=About%206000km%20of%20rivers%20and,Rhine%20Canal%2C%20completed%20in%201953

50. कोच्चि वाटर मेट्रो। 30 जून 2024 https://watermetro.co.in/about

51. अंतरर्राष्ट्रीय वित्त निगम। भारत के एमएसएमई को वित्तपोषित करना – भारत में एमएसएमई की ऋण आवश्यकता का अनुमान (पृष्ठ 65) https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/financing-india-s-msmes-estimation-of-debt-requirement-of-msmes-in-india.pdf

- सेवाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गए हैं। इसे देखते हुए, सरकार उपभोक्ता डेटा की सुरक्षा और सेवा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए डेटा सुरक्षा कानूनों और साइबर सुरक्षा नीतियों की दक्षता बढ़ा रही है। प्रौद्योगिकी को और अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनाने के लिए, मजबूत सुरक्षा उपायों को अपनाना, गोपनीयता विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देना आवश्यक है।

निष्कर्ष और भावी परिदृश्य

11.74 ऐतिहासिक रूप से, भारत का सेवा क्षेत्र कम लागत वाली पेशकशों पर फलता-फूलता रहा है। सेवाओं के डिजिटलीकरण और उचित नीतिगत पहलों ने पिछले दशक के शुरुआती दौर में सेवा वितरण की प्रकृति को लगभग अनुत्क्रमणीय रूप से लगातार रूपांतरित किया है। महामारी के बाद यह प्रवृत्ति और तेज हो गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एक और विशिष्ट पैटर्न जो उभरा है, वह यह है कि संपर्क-गहन व्यवसाय और व्यक्तिगत सेवाएँ - मुख्य रूप से व्यापार, परिवहन, रियल एस्टेट और उनकी सहायक सेवाएँ - जो महामारी के दौरान भारी गिरावट के दौर से गुजरी थीं, अब सुधार कर रही हैं, और उनमें ज़्यादा तकनीक और डिजिटल सामग्री समाविष्ट हो गई है। साथ ही, भारत के सेवा-निर्यात में सॉफ्टवेयर से आगे बढ़कर मानव संसाधन (एचआर), कानूनी और डिजाइन सेवाओं को शामिल करने के लिए विविधता आ रही है, जो उभरती वैश्विक माँगों के अनुरूप है। इस प्रकार, दो महत्वपूर्ण परिवर्तन घरेलू सेवा वितरण का तेज तकनीक-संचालित परिवर्तन और भारत के सेवा-निर्यात का विविधीकरण भारत के सेवा परिदृश्य को नया आकार दे रहे हैं।

11.75 देश वैश्विक क्षमता केंद्रों के हब के रूप में उभर रहा है। घरेलू स्तर पर, स्टार्ट-अप नवाचार को बढ़ावा देते हैं, ऋण, कच्चे माल और बाजारों तक पहुंच में सुधार करते हैं। गहन प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी-तंत्र और लगातार नीतिगत समर्थन की सहायता से, कई प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप विनिर्माण और अन्य सेवाओं का डिजिटलीकरण कर रहे हैं। गैर-सेवा आर्थिक गतिविधियों की अंतर्निहित सेवा सामग्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जैसा कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी द्वारा प्रमाणित हुआ है। इन गतिविधियों में उत्पादन के बाद का मूल्य संवर्धन भी ई-कॉमर्स, नवोन्मेष पैकेजिंग और विज्ञापन और आधुनिक संभार-तंत्र सेवाओं जैसी सेवाओं पर तेजी से निर्भर हुआ है।

11.76 जैसा कि भारत 2030 तक करोड़ों नौकरियां पैदा करने की उम्मीद कर रहा है, सेवाओं की मांग-आपूर्ति की गतिशीलता में इस परिवर्तन को मध्यम अवधि में भर्ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। सेवा क्षेत्र में उभरती नौकरी की माँग वृहत्तर और अधिक विशिष्ट कौशल को आवश्यक बनाती है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट[52] संज्ञानात्मक योग्यताओं (जैसे जटिल समस्या-समाधान और रचनात्मक सोच), डिजिटल साक्षरता और एआई और बड़े डेटा में दक्षता पर बढ़ते फोकस पर प्रकाश डालती है। यह बदलाव व्यवसायों और कार्यबल के लिए तकनीकी प्रगति के अनुकूल होने और वैश्विक बाजार की माँगों को पूरा करने के लिए रणनीतिक अनिवार्यता को रेखांकित करता है। फोकस क्षेत्रों में ब्लॉकचेन, एआई, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता, 3डी प्रिंटिंग और वेब और मोबाइल विकास शामिल होना चाहिए। अतः भारत में कौशल विकास कार्यक्रम का तात्कालिक कार्य इन आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए योजना बनाना और खुद को सुसजित करना है। कैपिटल इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि एआई के कारण भारत के सेवा-निर्यात की वृद्धि दर धीमी हो सकती है, तथा अगले दशक में इसमें प्रति वर्ष 0.3-0.4 प्रतिशत अंकों की कमी आ सकती है।[53] यह रोजगार सृजन के लिए अपेक्षाकृत कम कौशल-निर्भर पर्यटन क्षेत्र के महत्व को रेखांकित

52. विश्व आर्थिक मंच। (2023)। डब्ल्यूईएफ नौकरियों का भविष्य 2023 (पृष्ठ 7)। https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf

53. द इकोनॉमिस्ट (24 जून 2024)। क्या सेवाएं दुनिया को समृद्ध बनाएंगी? https://www.economist.com/finance-and-economics/2024/06/24/will-services-make-the-world-rich

करता है। इसलिए, सार्वजनिक नीति द्वारा पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सभी स्तरों पर सरकारों और निजी क्षेत्र को इस क्षेत्र की क्षमता को साकार करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।[54]

11.77 अल्पावधि में, अस्थायी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और कमोडिटी मूल्य अनिश्चितताएं इनपुट लागत और सेवाओं की मांग के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करती हैं।[55] इस प्रकार, सकारात्मक मांग प्रवृत्तियों को बनाए रखना और बढ़ती लागतों और प्रतिस्पर्धी दबावों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना आगामी वर्ष में सेवा क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण होगा। अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से सेवा क्षेत्र द्वारा दिखाई गई महामारी के बाद की गतिशीलता, इन अनिश्चितताओं और चुनौतियों को पार करने में मदद करेगी।

****

54. होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बेनोरी नॉलेज। विजन 2047: भारतीय होटल उद्योग (पृष्ठ 29)। https://hotelassociationofindia.com/Vision%202047%20-%20March%2030.pdf

55. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित 2019-20 के लिए नवीनतम आपूर्ति और उपयोग तालिकाओं के अनुसार, भारत में सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट कमोडिटी-उत्पादन (कृषि और औद्योगिक) क्षेत्रों से आते हैं। इसलिए, कमोडिटी की कीमतों पर दबाव सेवाओं की इनपुट लागत को और फलस्वरूप उनकी मांग को काफी प्रभावित कर सकता है।

यह पृष्ठ खाली छोड़ दिया गया है